



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2004/चैत्र 17, 1926

No. 84]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2004/CHAITRA 17, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004

विषय : चीन जनवादी गणराज्य और रूमानिया से कैल्सियम कार्बाइड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की अन्तिम समीक्षा संबंधी पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम।

सं. 15/1/2003-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. प्रक्रिया

1. अंतिम समीक्षा संबंधी जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों में यह अपेक्षा है कि वह समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करे। प्राधिकारी को मै0 श्रीराम विनायल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और रसायन उद्योग ने घरेलू उद्योग को जारी क्षति के मध्य नजर 5 वर्षों की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने का अनुरोध किया था।

- (ii) उक्त आवेदन का मैसर्स बिरला कार्बाइड, मै0 विप्रा इंडस्ट्रीज, मै0 रिजेंस कार्बाइड, मै0 वेंकटेश्वरा फैरो एलायस, मै0 पी ऐल एलायस और मै0 वीबीसी फैरो एलायस ने समर्थन किया ।
- (iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) और सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान और उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति का आकलन) नियमावली, 1995 के अनुसार इस बात की समीक्षा करने के लिए अन्तिम समीक्षा आरम्भ की कि क्या पाटनरोधी शुल्क को कम करने से पाटन तथा क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी तथा क्या चीन जनगण तथा रोमानिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्शियम कार्बाइड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता है ।
- (iv) प्राधिकारी ने दिनांक 20 जून, 2003 की सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जो चीन तथा रोमानिया (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्शियम कार्बाइड पर पाटनरोधी शुल्क की अन्तिम समीक्षा संबंधी पाटनरोधी जांच आरम्भ किए जाने के बारे में थी । कैल्शियम कार्बाइड का सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क शीर्ष 284910 के तहत वर्गीकरण किया गया है ।
- (v) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए) तथा उद्योग संघों को दी थी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया था ।
- (vi) प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में कैल्शियम कार्बाइड के सभी ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति प्रेषित की थी और उन्हें पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था ।
- (vii) प्राधिकारी ने सभी इच्छुक पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से 30 सितम्बर, 2003 को प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया । अपने-अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। इन

पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतिलिपियां एकत्र करें और उन पर अपने-अपने खंडन, यदि कोई हों दें ।

(viii) प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों तथा संबंधित देशों के दूतावासों को उक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक-एक प्रति दी थी । अब हितबद्ध पार्टियों को भी, जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था, याचिका की एक-एक प्रति दी गई थी ।

(ix) संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेज दें । निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की एक-एक प्रति भी सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची सहित दूतावास को भेज दी गई थी ।

(x) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के भारत में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/उत्पादकों को एक-एक प्रश्नावली भेजी गई थी:-

1. कार्बाइड-फॉक्स एस.सी.ए., रोमानिया
2. कोचिम एस.ए. रोमानिया
3. मै0 टीटीसी, एवं मै0 शांक्सी फुगु, चीन
4. मुंजाल गैसिस -लुधियाना
5. पूना ऑक्सीजन एंड एसीटीलीन कं0 प्रा0 लि0
6. नेशनल ऑक्सीजन लि0, चेन्नई
7. एसियाटिक गैसिस लि0, थाणे
8. मेप्रो इंडस्ट्रीज लि0, मुम्बई
9. बोम्बे ऑक्सीजन कार्पो. लि0, मुम्बई
10. अक्षर एसीटीलीन लि0, गुंजरात
11. बीओसी गैसिज, कलकत्ता
12. ग्वालियर एयर प्रोडक्ट्स लि0, एम.पी.

13. बिरला कार्पो. लि०, बिरला कार्बाइड की एक इकाई, केयर/आफ ए.के. गुप्ता
14. टीईसीआईएल
15. आईसीएमएल
16. पंयाम
17. ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसिज मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
18. डीसीडब्ल्यू लि०, नई दिल्ली
19. सेनका कार्बन प्रा० लि०, चेन्नई
20. श्रीराम विनाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली
21. रिजेंसी कार्बाइड प्रा० लि०, पाओंटा साहिब (हि.प्र.)
22. वेंकटेश्वर फेरो एलायस प्रा० लि०, हिमाचल प्रदेश
23. हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पाओंटा साहिब
24. पीईई ईएलएल एलाय प्रा० लि०, नई दिल्ली
25. बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई ।
26. वीबीसी फेरो एलायस लिमिटेड, हैदराबाद
27. मै० चैमप्लास्ट सन्मार
28. मै० जमशेदपुर इंजेक्शन पॉवर लि०
29. मै० विप्रा इंडस्ट्रीज लि०

मै० श्रीराम के अतिरिक्त निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर दिया:-

- क) डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, नई दिल्ली
- ख) सेनका कार्बन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई
- ग) मै० चैमप्लास्ट सन्मार
- घ) मै० टीटीसी, एवं मै० शांक्सी फुगु, चीन

हालांकि मै० बिरला कार्बाइड, मै० विप्रा इंडस्ट्रीज, मै० रिजेंसी कार्बाइड, मै० वेंकटेश्वर फेरो एलायस, मै० पी एल एलायंस और मै० वीबीसी फेरो एलायस द्वारा याचिका का समर्थन किया गया था लेकिन इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली का कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

- xi. क्षति के बारे में अतिरिक्त सूचना याचिकाकर्त्ताओं से मांगी गई थी । उक्त सूचना भी उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी ।
- xii. प्राधिकारी ने कैल्शियम कार्बाइड के भारतीय उत्पादकों और मै0 टीटीसी ऐंड मै0 शांक्सी फुगु, चीन के परिसरों पर मौके पर जाकर जांच की थी ।
- xiii. प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के गैर-गोपनीय अंश वाली कायम सार्वजनिक फाइल को इच्छुक पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा गया था ।
- xiv. अनुकूल उत्पादन लागत और सामान्यीकृत स्वीकृत लेखा सिद्धांतों(जीएएपी) तथा याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर विनिर्माण लागत तथा भारत में संबद्ध माल की बिक्री के आंकलन के प्रयोजनार्थ लागत जांच भी की गई ताकि यह पता चल जाए कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।
- xv. इस अधिसूचना में किसी इच्छुक पक्षकारा द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी शामिल है और प्राधिकारी ने नियमावली के तहत उसी पर विचार किया ।
- xvi. उपर्युक्त अनुबंधों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचारार्थ वाले आवश्यक तथ्य शामिल हैं जिसे अन्तिम जांच परिणामों के परियोजनार्थ आधार रूप माना गया है । वक्तव्यों को बार-बार प्रस्तुत करना किसी तथ्य/तर्क को या तो स्वीकार करने अथवा रद्द करने के समान नहीं है । इच्छुक पक्षकारों द्वारा मौखिक सुनवाई के समय किए गए तर्कों को इस प्रकटन वक्तव्य में परिलक्षित इस सीमा तक किया गया है जिससे उन पर इस जांच के संगत विचार किया जा सके ।
- xvii. उपर्युक्त के नहीं होते हुए भी इस प्रकटन वक्तव्य में दिए गए सभी तथ्य (गोपनीय आधार पर प्रस्तुत तथ्यों सहित) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्तिम निर्णय के उद्देश्य से गुणावगुण आधार पर प्रस्तुत सभी उत्तरों पर विचार करेगा ।

xviii. उक्त जांच 1 अक्टूबर, 2001 से 31 मार्च, 2003 (18 महीने) की जांच अवधि के लिए की गई ।

xix. प्रकटन वक्तव्य के प्रत्युत्तर दिनांक 26 मार्च, 2004 के निम्नलिखित से प्राप्त हुए:-

(क) घरेलू उद्योग. ।

(ख) मै0 डीसीडब्ल्यू, मै0 केमप्लास्ट और मै0 सेनका(आयातक/औद्योगिक प्रयोक्ता) की ओर से मै0 ईएलपी ।

(ग) मै0 जमशेदपुर इंजेक्शन पॉवर लिमिटेड (प्रत्युत्तर दिनांक 26 मार्च, 2004 की निर्धारित तिथि के बाद दिनांक 29.5.2005 को प्राप्त हुआ)

xix. निम्नलिखित संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल किया गया:

कार्बाइड

कैल्शियम कार्बाइड

चीन

चीन जनवादी गणराज्य

प्राधिकारी

निर्दिष्ट प्राधिकारी

अम.डा.

अम.डालर(1 अम.डालर= 48.59 रु

और 1 अम.डा.= आरएमबी 8.26)

पीओआई

जांच अवधि

अंतिम निष्कर्ष/मूल मामला/

चीन जनवादी गणराज्य और

जांच

रोमानिया से कैल्शियम कार्बाइड के आयात के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना सं0 27/1/97-एडीडी, दिनांक 22 जनवरी, 1999.

2. घरेलू उद्योग, निर्यातकों तथा आयातकों के विचार

2(क) घरेलू उद्योग के विचार:

- (i) निर्यातक उन कीमतों पर कीमत वचनबद्धता दे सकता है जिन पर माल का आयात किया गया अथवा अक्षतिकारी कीमत पर ।

- (ii) पाटनरोधी शुल्क पूर्णतया अपर्याप्त है और इसलिए इन शुल्कों को बढ़ाया जा, तथा इसे अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुशंसित किया जाए ।
- (iii) याचिकाकर्ता तथा घरेलू उद्योग मै0 श्रीराम को चीन जन.गण तथा रोमानिया से संबद्ध माल के पाटित आयात की वजह से क्षति हो रही है ।
- (iv) मै0 श्रीराम ने गहरे समुद्र बिक्री के आधार पर कोई बिक्री नहीं की है यद्यपि उसने अपने जरूरत के लिए कुछ कैल्शियम कार्बाइड का आयात किया है । याचिकाकर्ता ने कैल्शियम कार्बाइड का कोई भी निर्यात नहीं किया है ।
- (v) शुल्कों की अमरीकी डालर में सिफारिश की गई है ।
- (vi) सभी 15 कारकों की जांच चीन से संबंधित एमईटी संबंधी आंकड़ों को स्वीकार करने से पहले किए जाने की आवश्यकता है ।
- (vii) निर्यातकों द्वारा अपर्याप्त जानकारी दर्ज की गई है ।
- (viii) चीन में बिजली की कीमतें 4 रू० प्रति यूनिट के बराबर है ।
- (ix) नियम 11(3) को क्षेत्रीय आधार पर अनुशंसित शुल्क के लिए लागू नहीं किया जा सकता है ।

2.1(क) प्रकटन वक्तव्य के जारी होने के पश्चात् घरेलू उद्योग के विचार

.....याचिकाकर्ता को लगता है कि प्रकटन वक्तव्य में निम्नलिखित निर्णय हैं-

- (क) याचिकाकर्ता उक्त नियमावली के अर्थ के तहत घरेलू उद्योग है ।
- (ख) चीन तथा रोमानिया के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है । इन दोनों देशों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी है। इस प्रकार निर्यातकों ने उक्त माल का पाटन जारी रखा और पाटनरोधी शुल्क पुनः समाप्त करने से पाटन की पुनरावृत्ति जारी रहेगी ।
- (ग) क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता प्रकटन वक्तव्य को नोट करता है और यह निवेदन करता है कि:
 - (i) कीमत कटौती चीन के संबंध में 10-20 % और रोमानिया के संबंध में 30-40% है ।
 - (ii) हालांकि कुल आयातों तथा मांग के संबंध में आयातों में गिरावट आई है परन्तु निवेदन है कि आयातों में यह गिरावट पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण आई है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना

औचित्यपूर्ण है। पाटनरोधी शुल्क के अभाव में आयातों में और आगे वृद्धि होना स्वाभाविक होगा।

- (iii) यह पाया गया है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उत्पादन लागत की गणना दोबारा की गई है। याचिकाकर्ता मानते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उत्पादन लागत में किए गए समायोजन अपनाए जा रहे कानूनी उपबंधों, प्रक्रिया तथा पद्धतियों के अनुकूल नहीं हैं, यह अवांछित है और इस मामले के विशेष तथ्यों तथा परिस्थितियों के संगत नहीं है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विद्युत कीमत वार्षिक रिपोर्ट में दी गई बिक्री कीमत के आधार पर समझी है। लेकिन माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को संगत जानकारी देने के लिए कभी नहीं कहा है। यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता बिजली की बिक्री तब करता है जबकि वह अपने संयंत्र में विद्युत का उपयोग नहीं कर सके। यह नोट किया जाना चाहिए कि जांच अवधि के दौरान कंपनी द्वारा बेची गई बिजली जांच अवधि में उत्पादित कुल विद्युत का अनुकूल हिस्सा है।

माननीय सेसटैट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य(पीटीए के संबंध में) के मामले में यह निर्णय दिया था कि विद्युत कीमत लागत जमा लाभ के हिसाब से ली जाए। इस प्रकार, प्रस्तावित पद्धति माननीय सेसटैट के निर्णय के अनुकूल नहीं है। याचिकाकर्ता यह समझता है कि माननीय सेसटैट के निर्णय माननीय प्राधिकारी पर बाध्य हैं।

- (iv) घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्से में वृद्धि यह जांच करने के संगत नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में पुनरावृत्ति नहीं होगी। यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में अपने उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा तथा बाजार हिस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा क्योंकि यह साबित हो गया है कि आयातों की लैंडिड कीमत निबल बिक्री वसूली की तुलना में बहुत ही कम है।
- (v) घरेलू उद्योग की वृद्धि तथा आरओआई जो कि पहले सकारात्मक रहे थे, उसमें चालू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के मामले में क्षति होगी क्योंकि आयात की लैंडिड कीमत निबल बिक्री वसूली की

तुलना में बहुत ही कम है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने तथा उसके प्रभाव संगत कारक का होना है न कि संदर्भाधीन अवधि में घरेलू उद्योग का वास्तविक कार्य-निष्पादन।

- (vi) जहां घरेलू उद्योग यह समझता है कि उसे वित्तीय हानि हो रही है वहां माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह रोक है कि घरेलू उद्योग को लाभ हुआ है, ऐसा संशोधित उत्पादन लागत के आधार पर दिखाई देता है जबकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिना किसी पर्याप्त आधार और कारण के तथा माननीय सेसटैट के निर्णय के विरुद्ध घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में संशोधन किया है। किसी भी परिस्थिति में उक्त अवधि के दौरान लाभ का होना पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का ओचित्य बनता है क्योंकि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग कीमतों और उसके बाद लाभ पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा।
 - (vii) हालांकि घरेलू उद्योग कुछ कीमत वृद्धि प्राप्त कर सकता था लेकिन सकारात्मक तथा पर्याप्त कीमत कटौती की वजह से यह निश्चित है कि घरेलू उद्योग मौजूदा कीमतों पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा।
 - (viii) घरेलू उद्योग के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में नुकसान होगा।
 - (ix) चीन में कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन कर रहे संयंत्रों की बहुत बड़ी संख्या होने के कारण देश में काफी घरेलू खपत होने के बावजूद बेशी कार्बाइड अभी भी मौजूद है।
- (घ) घरेलू उद्योग का निवेदन है कि मौजूदा जांच अंतिम समीक्षा जांच के रूप में है। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की जांच अंतिम समीक्षा की जरूरतों के संदर्भ में अपेक्षित है। इस संबंध में याचिकाकर्ता का निवेदन है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी सीमा तक पहले ही कटौती हो रही है। यदि मौजूदा शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कीमत कटौती में और आगे भी वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप और अधिक आयात होने की संभावना है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हो रहा था और इस बात की प्रबल संभावना है कि पाटनरोधी उपायों के बिना संबंधित उत्पाद की अधिक मात्रा भारतीय बाजार में बहुत ही कम कीमतों पर

भेज दी जाएगी जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होगी और उसके फलस्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति होगी ।

प्रकटन वक्तव्य में निर्णय है कि संबद्ध देशों में उत्पादन क्षमता, विशेष रूप से चीन में विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक है ।

चूंकि मौजूदा शुल्क इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं और वह पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की तुलना में बहुत ही कम हैं, इसलिए निवेदन है कि इन उपायों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप देश में इस उत्पाद का और अधिक आयात होगा । इस प्रकार, इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की पुनरावृत्ति होगी ।

- (ड.) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने^१ भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दों नामक शीर्षक के तहत प्रकटन वक्तव्य के पैरा 12 में कतिपय रोक लगाई हैं । यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह रोक इच्छुक पक्षकारों के विचार हैं अथवा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचार । किन्तु, याचिकाकर्ता समझता है कि ये रोक मौजूदा जांच के संगत नहीं हैं । उदाहरण के लिए मांग के संबंध में यह स्वीकार किया जाता है कि कार्बाइड की मांग में सकारात्मक रूप दर्शाया गया है जोकि एकमात्र संगतकारक बनता है । यह रोक कि कतिपय वैल्विंग कामों के लिए एलपीजी के अधिक प्रयोग से इस उत्पाद की मांग में कुछ प्रभाव पड़ेगा, किसी जांच के बिना प्रतीत नहीं होता है लेकिन यह अनावश्यक है क्योंकि प्राधिकारी के पास एकमात्र संगत कारक यह है कि क्या मांग में वृद्धि अथवा गिरावट दर्शाई गई है । यह रोक कि पी वीसी के उत्पादन के लिए कार्बाइड का प्रयोग आवश्यक रूप से कम कार्यकुशल है और यह अटकलों पर आधारित है, विशेष रूप से तब जबकि याचिकाकर्ता अपने मार्ग से पीवीसी का उत्पादन करता रहा है और वह यह नहीं समझता है कि यह मार्ग कम कार्यकुशल है ।

कार्बाइड की मौजूदा कीमतों के संबंध में माननीय प्राधिकारी का संदर्भ प्राधिकारी की साबित पद्धति के प्रतिकूल है कि जांच अवधि के बाद की गतिविधियाँ संगत नहीं हैं और माननीय प्राधिकारी ने ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति की है जैसाकि मैटकोक के मामले में की गई थी, जहां प्राधिकारी ने उस उत्पाद की आसमान छूती कीमतों को मध्यनजर रखने से इंकार कर दिया था, इसे जांच अवधि के बाद की गतिविधियों में शामिल किया था ।

प्रकटन वक्तव्य इस बात का स्वयं विरोध करता है जहां उसमें एक जगह कहा गया है कि कार्बाइड के मार्ग के ज़रिए पीवीसी का उत्पादन कम कार्यकुशल प्रतीत होता है और उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता बड़े विस्तार करना चाहता है। उसमें बड़ा विस्तार करने संबंधी तर्क का विरोध किया गया है कि यह मार्ग कार्यकुशल नहीं है। यह वक्तव्य कि 'कार्बाइड की लघु मात्रा का उत्पादन कर रहे लघु उद्योग एककों का कम एसिटिलीन उत्पादन है, भी अटकल बाजी पर आधारित है और यह रिकॉर्ड के अनुसार गैर-साबित साक्ष्य है।

अक्षतिकारी कीमत: याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के लिए प्रस्तावित अक्षतिकारी कीमत 19329 रू० प्रति मी.टन. के प्रति बहुत ही चिंतित है। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि यह निर्धारण उत्पादन लागत में अनुपयुक्त, अस्वीकार्य बदलाव किए जाने के बाद किया गया है और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (पीटीए से संबंधित, दोनों स्पेन तथा कोरियाई मामले) के मामले में माननीय सेसटैट के निर्णयों के विरुद्ध है

'.....इस प्रकार यह साक्ष्य मौजूद है कि अक्षतिकारी कीमत का ठीक से आकलन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि पूंजी लागत को जोड़कर विद्युत उत्पादन की लागत और यथोचित लाभ (उत्पाद तथा विद्युत पर) को ध्यान में रखते हुए और कंपनी द्वारा प्रतिष्ठापित सकल परिसंपत्तियों पर विचार करते हुए अक्षतिकारी कीमत का पुनः आकलन किया जाए। याचिकाकर्ता ने ऐसा कर लिया है और यह पाया है कि कंपनी द्वारा लगाई गई सकल परिसंपत्तियों पर यथोचित लाभ तथा विद्युत लागत को मद्देनजर रखते हुए अक्षतिकारी कीमत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अक्षतिकारी कीमत की तुलना में कहीं अधिक बैठती है।

(च) अक्षतिकारी कीमत की तुलना में अधिक निबल बिक्री वसूली में 'कोई क्षति नहीं' शामिल नहीं है।

मौजूदा जांच अंतिम समीक्षा जांच है। अंतिम जांच के तहत पाटन तथा क्षति को 'जारी रखना' अथवा 'उसकी पुनरावृत्ति' की अपेक्षा है। माननीय प्राधिकारी द्वारा यह पहले ही साबित कर दिया गया है कि उक्त उत्पाद की बिक्री पाटन कीमतों पर जारी है। अतः एकमात्र संगत मुद्दा यह बनता है कि

पाटन के कारण क्षति हो रही है। इस संबंध में यह तथ्य कि निबल बिक्री वसूली अक्षतिकारी कीमत की तुलना में अधिक रही है, केवल इस बात को सर्वोत्तम सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को कोई 'जारी' क्षति नहीं हुई है। यह इस बात को साबित नहीं करता है कि 'घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति नहीं होगी' याचिकाकर्ता का निवेदन है कि यदि आयातों की लेंडेड कीमत निबल बिक्री वसूली तथा अक्षतिकारी कीमत की तुलना में काफी कम रहती है तो निष्कर्ष यह होना चाहिए कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होगी। पर्याप्त कीमत कटौती में यह बात समाविष्ट है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सकारात्मक क्षति मार्जिन में यह समाविष्ट है कि घरेलू उद्योग को बिक्री अक्षतिकारी कीमत की तुलना में कम कीमत पर करने को बाध्य होना पड़ेगा और यहां तक कि घरेलू उद्योग को बराबर की कीमतों पर बिक्री करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार, सकारात्मक कीमत कटौती तथा क्षति मार्जिन के होने पर याचिकाकर्ता का निवेदन है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

प्राधिकारी द्वारा जांच (उपरोक्त 2.1 क)

- (क) अक्षतिकारी कीमत का घरेलू उद्योग को गोपनीय आधार पर खुलासा किए जाने के बाद, विशेष रूप से विद्युत लागत तथा परिसम्पत्तियों के आंकलन के संबंध में लागत निर्धारण के प्रत्येक कारक के संबंध में घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत के निर्णय संबंधी ब्यौरे बता दिए गए थे। प्राधिकारी के रूख में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विश्वास किया।
- (ख) क्षतिकारकों का आंकलन घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर और सत्यापन के दौरान एकत्र वार्षिक रिपोर्ट तथा आंकड़ों में मै0 श्रीराम के दावों के आधार पर किया गया। विस्तृत आंकलन इस जांच परिणाम के पैराग्राफ 11 के तहत कवर किया गया है।
- (ग) मै0 श्रीराम की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट (2001-02) में यह दावा है कि 'एलपीजी द्वारा स्थानापन्न को देखते हुए मांग में भी गिरावट का रूख रहा है।' इस पर प्राधिकारी ने अपने विशेष निष्कर्ष के प्रयोजनार्थ विश्वास किया है।
- (घ) किसी भी समर्थनकारी घरेलू उत्पादक ने समान उत्पाद, उसके प्रयोग अथवा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नावली पर कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यह जानकारी प्रयोक्ता उद्योग से ही प्राप्त हुई।

- (ड.) घरेलू उद्योग ने प्रकटन वक्तव्य के प्रत्युत्तर में शामिल तथ्य पर अपनी सहमति व्यक्त की कि क्षति कारक के आकलन से साबित होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी नहीं रही है। जहां तक क्षति की पुनरावृत्ति का संबंध है इस जांच परिणाम के पैरा 11 के तहत अलग से कारकों की जांच की गई है।
- (च) कार्बाइड के गैस उत्पादन और पीवीसी के उत्पादन तथा बाजार का मुद्दा आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- (छ) प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद की अवधि संबंधी जानकारी पर क्षति के आंकलन के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया और इसका हवाला उस समय दिया जब भारतीय उद्योग के हित के मुद्दों का वर्णन किया गया है।

2(ख) निर्यातक/आयातक/प्रयोक्ता के विचार

(i) मै0 कार्बिड-फोक्स रोमानिया

- (क) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात् भारत को कार्बाइड निर्यात 17% से घटकर 3.23% रह गया।
- (ख) रोमानिया द्वारा केवल गैर-परम्परागत किस्म के कार्बाइड की डिलीवरी की जाती है।
- (ग) जिन कीमतों पर भारत को सप्लाई की जाती है वे सामान्य हैं तथा वे चीन के उद्भव के कैल्शियम कार्बाइड की कीमतों की तुलना में कहीं अधिक है।
- (घ) '...उत्पादन, निर्यात, कीमतों, डिलीवरी मार्कर, आदि से संबंधित जानकारी पर हम उसे गोपनीय मानते हुए सभी मामलों में प्रदान नहीं कर सकते हैं।

2.1(ख) प्रकटन वक्तव्य के जारी होने के पश्चात मै0 कार्बिड फोक्स के विचार

प्रकटन वक्तव्य के पश्चात मै0 कार्बिड फोक्स ने एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि मै0 कार्बिड फोक्स ने दिनांक 20 जून, 2003 से 17 मार्च, 2004 (प्रकटन वक्तव्य जारी होने की तारीख) की जांच-अवधि कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

(ii) मै0 टीटीसी तथा मै0 शांक्सी फुगु: चीन और आयातक

- (क) याचिका की अगोपनीय जानकारी पूर्णतया अपर्याप्त है।
- (ख) मै0 श्रीराम व्यापार प्रयोजनों के लिए एक आयातक है।
- (ग) घरेलू उद्योग की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

- (घ) विचाराधीन उत्पाद रेडियोएक्टिव माल नहीं है ।
- (ङ.) संबद्ध माल के सामान्य मूल्य का निर्धारण वास्तविक लागतों के आधार किया जाना चाहिए और चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए ।
- (च) कैल्शियम कार्बाइड की अत्यंत कमी है । पाटनरोधी शुल्क के विद्यमान रहने के बावजूद आयातक चीन से कार्बाइड का आयात कर रहे हैं ।
- (छ) दक्षिण भारत में कार्बाइड का कोई भी उत्पादक नहीं है जो दक्षिण भारत में कार्बाइड के प्रयोक्ताओं पर प्रभाव डाले ।
- (ज) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जनहित का ध्यान रखा जाना चाहिए ।
- (झ) घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति नहीं हुई है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े भ्रामक हैं ।
- (ट) पाटित माल तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं बनता है ।
- (ठ) नियम 11(3) द्वारा दक्षिण भारत में विभिन्न प्रोक्ताओं (बाजार) को विशेष तथा अलग-अलग व्यवहार प्रदान किया जाए ।
- (ड) मै0 श्रीराम की बिजली लागत को ठीक से परिलक्षित नहीं किया गया है ।
- (ढ) अंतर्राष्ट्रीय तथा चीन की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित हैं ।
- (ण) डीजीसीआईएस के व्यापार आंकड़ों पर विचार किया जाए ।
- (त) घरेलू औद्योगिक प्रयोक्ता मै0 श्रीराम से खरीद के लिए यह मानकर इच्छुक हैं कि वे उचित कीमत निर्धारण करते हैं और वे बड़ी-बड़ी मात्रा समयबद्ध तरीके से स्वीकार करते हैं ।
- (थ) असहयोगी कंपनी को अवशिष्ट श्रेणी प्रदान नहीं की जानी चाहिए ।
- (द) और आगे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाए ।

2.1(ख) प्रकटन वक्तव्य के जारी होने के पश्चात् आयात/प्रयोक्ताओं के विचार

'....उपर्युक्त के संदर्भ में आयातकों/औद्योगिक प्रयोक्ताओं की ओर से निम्नलिखित निवेदन किए जाते हैं:-

1. गोपनीय जानकारी:

- क) सबसे पहले इस बात पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि याचका में प्रस्तुत जानकारी और कार्रवाई के प्रत्येक स्थान पर यह विकट रूप से अपर्याप्त रही है और इससे औद्योगिक प्रयोक्ताओं को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों का मुकाबला करने हेतु अवसर नहीं मिला है । विशेष

रूप से निम्नलिखित बातें औद्योगिक प्रयोक्ताओं को प्रदान नहीं की गई:-

- लागत निर्धारण जानकारी के सूचीकृत फारमेट याचिका के साथ प्रस्तुत की जाए ।
- प्रभाग-वार तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे याचिकाकर्ता द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन से संबंधित हों ।
- याचिकाकर्ता की एनआईपी के निर्धारण संबंधी पद्धति, विशेषरूप से ऊपरी लागतों तथा बिजली की लागत का संविभाजन ।
- याचिकाकर्ता द्वारा कैप्टिव रूप से खपत से वसूली ।

उपर्युक्त में से प्रत्येक मुद्दा जांच की तह तक जाता है और इन मुद्दों का अप्रकटन औद्योगिक प्रयोक्ताओं के विरुद्ध जाता है ।

2. घरेलू उद्योग तथा मांग

- (क) सबसे पहले यह कहा जाए कि घरेलू उद्योग के संगठन के संबंध में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन कारक अधिकांश रूप से अबोधगम्य हैं ।
- (ख) उपरोक्त के पूर्वाग्रह के बिना यह सादर प्रस्तुत है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण हैं । माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि मैसर्स श्रीराम और उसक समर्थक मै० वीबीसी फैंरो एलायस तथा मै० बिरला कार्बाइड अतर्कसंगत हैं । वास्तव में, बाद वाली दोनों कंपनियां जांच-अवधि के दौरान उत्पादन नहीं कर रही थी । रिकॉर्ड के प्रयोजनार्थ इन दोनों समर्थक कंपनियों ने जांच अवधि से तथा जांच अवधि के दौरान कैल्शियम कार्बाइड का कोई उत्पादन नहीं किया है । उनकी प्रतिस्थापित क्षमता को देखते हुए और उन्हें घरेलू उद्योग का दर्जा दिया जाना भारत में कैल्शियम कार्बाइड के उपभोक्ताओं का उपहास करना है ।
- (ग) स्पष्टरूप से, देश में भारी मांग सप्लाई अन्तर है । गैर-उत्पादकों को घरेलू उद्योग का दर्जा देकर माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत के कैल्शियम कार्बाइड के उपभोक्ताओं को अत्यन्त हानि पहुंचा रहे हैं ।

3. चीन से सामान्य मूल्य का निर्धारण

- (क) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया है कि चीन के सत्यापन दौरे के दौरान इस कार्रवाई में सहयोग करने वाला एकमात्र निर्यातक कार्रवाई के दौरान प्रस्तुत लागतों की पड़ताल हेतु उपयुक्त ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सका है।
- (ख) यह सादर प्रस्तुत है कि कैल्शियम कार्बाइड के औद्योगिक प्रयोक्ताओं को एक गंभीर धक्का लगा है। दूसरे निर्यातकों ने इस कार्रवाई में सहयोग करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। एकमात्र निर्यातक की अर्हता समाप्त करके माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अगले पांच वर्षों के लिए शुल्क जारी रखने का मानदंड निर्धारित किया है।
- (ग) यह सादर निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह सहयोगकर्ता निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का सम्मान करे। नियम 6(8) के तहत जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था है -

किसी ऐसे मामले में जिसमें इच्छुक पक्षकार इस बात के लिए मना करता है अथवा अन्यथा आवश्यक जानकारी यथोचित समयावधि के भीतर प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में काफी बाधा उत्पन्न करता है वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड कर सकता है और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिश दे सकता है जैसाकि उसे ऐसी परिस्थितियों में ठीक लगता हो,

माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात के लिए पूर्णतया सक्षम हो कि वह स्वतंत्र लागतों का उपयोग करे, जैसे विद्युत लागत, परिवहन, पैकेजिंग, आदि जोकि चीन में विद्यमान हों और जिसे सहयोगकर्ता निर्यातक ने आंशिक रूप में प्रदान किया हो क्योंकि वह स्वतंत्र बीजकों के आधार पर होगी।

- (घ) यह विनम्र अनुरोध है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी इन मूल्यों पर विचार करे क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लागतों पर आधारित कोई भी परिणामी लागत समाप्त हो जाएगी।

4. क्षति:

- (क) यह सादर निवेदन है कि याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है बल्कि इसके विपरीत उसे रिकॉर्ड आय प्राप्त हुई है।
- (ख) सर्वप्रथम औद्योगिक प्रयोक्ता दिनांक 10 मार्च, 2004 के पत्र द्वारा निवेदनों को दोहराना चाहेंगे। विशेष रूप से औद्योगिक प्रयोक्ता रिकॉर्ड में उस प्रैस रिलीज को शामिल करवाना चाहेंगे जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा योजनाबद्ध लाभ तथा विस्तार का रिकॉर्ड दर्शाया गया है। स्पष्ट रूप से, यह क्षति का मुकाबला कर रहे किसी कंपनी का लक्षण नहीं है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि तथा उसके अनुबंध को अनुबंध-I में प्रस्तुत किया गया है।
- (ग) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रिकॉर्ड किया है कि जांच अवधि के दौरान -

- उत्पादन अधिक है।
- क्षमता उपयोग में वृद्धि है।
- कैप्टिव खपत में वृद्धि है।
- प्रारंभिक स्टॉक कम है।
- बिक्री कीमत अधिक है।
- दैनिक उत्पादन अधिक है।
- लगाई गई पूंजी कम है।
- प्रतिदिन घरेलू बिक्री में वृद्धि है।
- कारोबार अधिक है।
- बिक्री मात्रा अधिक है।

उपर्युक्त के मद्देनज़र सादर निवेदन है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और तदनुसार शुल्क वापस लिया जाए।

5. कारणात्मक संबंध:

- (क) उपर्युक्त के संदर्भ में सादर निवेदन है कि याचिकाकर्ता की क्षति, यदि कोई है चीन अथवा रोमानिया से तथाकथित पाटन के कारण नहीं हुई है।
- (ख) आयात मात्रा में गिरावट आई है। वास्तव में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट नहीं किया है कि चीन के मामले में व्यापार बाजार के हिस्से में गिरावट 25.22% से घटकर 10.45% हो गई है। रोमानिया के मामले में बाजार हिस्सा 3.21% से घटकर 0.81% हो गया है। इसी तरह, याचिकाकर्ता का हिस्सा बढ़ गया है और अब यह 25% से अधिक है। इसी प्रकार, कुल मांग में चीन का हिस्सा 15.82% से घटकर 6.09 रह गया है और रोमानिया का हिस्सा 2.01% से घटकर 0.47% रह गया है। याचिकाकर्ता का हिस्सा 56% से भी अधिक है, इस प्रकार याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा 82% से भी अधिक है। यह कमोबेश नोट करने लायक तथ्य है कि याचिकाकर्ता ही देश में कैल्शियम कार्बाइड का एकमात्र उत्पादक है क्योंकि अन्य कंपनियां अन्दरूनी कठिनाइयों अथवा बिजली की उच्च लागतों के कारण बन्द हो गई हैं।
- (ग) इसके अलावा, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को भूटान से होने वाले निर्यातों की भूमिका पर विचार करना चाहिए - भूटान से होने वाले निर्यात का बाजार हिस्सा अच्छा खासा है और भूटान से कैल्शियम कार्बाइड का लैंडेड मूल्य यद्यपि अधिक है लेकिन यह भारत में सीवीडी (उत्पाद शुल्क) को आकर्षित नहीं करता है और इस प्रकार यह लगभग उसी कीमत पर बैठता है जिस पर यह चीन तथा रोमानिया के माल पर।

6. हाल में हुई गतिविधियाँ, क्षति तथा उसकी आशंका:

- (क) इस बात का उल्लेख किया जाए कि हाल के महीनों में चीन से कैल्शियम कार्बाइड की लागत सीआईएस आधार पर 450 अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ संलग्न अनुबंध-II में वास्तविक बीजों (गोपनीय) के आंकड़े हैं जिनमें

औद्योगिक प्रयोक्ताओं द्वारा हाल में किए गए आयात ब्यौरे दर्शाए गए हैं ।

- ख) अनुबंध-III में चीन से प्राप्त हाल ही के कोटेशन दिए गए हैं ।
- ग) इसके अलावा, संलग्न अनुबंध-IV (गोपनीय) में विभिन्न सप्लायरों के पत्र आदि हैं जिसमें चीन के विलंबित पोतलदान तथा कमियाँ दर्शायी गई हैं ।
- घ) यह एक तथ्य है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से इस बात की पड़ताल कर सकते हैं कि चीन की सरकार ने दक्षिण कोरिया मूल के और चीन को निर्यातित कैल्शियम कार्बाइड पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है । इसके परिणामस्वरूप चीन में कैल्शियम कार्बाइड का समस्त घरेलू उत्पादन चीन में पीवीसी उत्पादन के प्रयोजनार्थ विविधीकृत किया गया है और निर्यात बाजार में सप्लाय हेतु कमी है । इसके अलावा, चीन के घरेलू बाजार में कैल्शियम कार्बाइड की सप्लाय बढ़ाने के उद्देश्य से चीन की सरकार ने वैट प्रोत्साहन समाप्त कर दिए हैं जो निर्यातकों को दिए जा रहे थे और इसी प्रकार, भारत में इस्पात निर्यातकों को डीईपीबी को वापस ले लिया गया था ।
- ड.) औद्योगिक प्रयोक्ताओं पर पिछले पांच वर्षों से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है (माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस अंतिम समीक्षा तक प्रारंभिक पांच वर्षों के बाद के लिए बढ़ा दिया है) और अब कीमतें अत्यधिक ऊँची हो गई हैं

प्राधिकारी की जांच(उपर्युक्त 2.1 ख)

- ◆ प्रकटन विवरण-पत्र में अक्षतिकारी कीमत, लैंडेड मूल्य, निबल बिक्री वसूली की सभी पद्धतियों को विस्तार से व्यक्त किया गया है ।
- ◆ पूर्ण क्षति चार्ट समयानुसार आवश्यक तथ्य के रूप में प्रकट किया गया । घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित प्रश्नावली (सार्वजनिक रूप से उपलब्ध) में फार्म सी-1 तथा सी-2 हैं जो स्पष्ट रूप से प्राधिकारी द्वारा ऊपरी लागतों के संविभाजन के लिए अपनाई गई पद्धति की ओर इंगित करते हैं । पाटनरोधी आवेदन-पत्र के प्रपत्र के पैरा 6(सामान्य) के अनुसार जानकारी को गोपनीयता प्रदान की गई है ।

निर्यातक को सत्यापन के तुरंत बाद सत्यापन के दौरान प्राधिकारी की आख्याओं की सूचना दी गई थी।

- ◆ घरेलू उद्योग को जारी प्रकटन विवरण-पत्र में घरेलू उद्योग को गोपनीय आधार पर सूचित अक्षतिकारी कीमत के ब्यौरे दिए गए हैं।
- ◆ निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य के निर्णय तथा ब्यौरों की पद्धति का विशेष खुलासा निर्यातक को उपलब्ध करा दिया गया है।

2.2(ख) उठाए गए शेष मुद्दों के प्रत्युत्तर विचाराधीन उत्पाद, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षति का आकलन तथा कारणात्मक संबंध और भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दों के विशेष शीर्षों के तहत शामिल किए गए हैं।

2.3 जेमिपोल(प्रयोक्ताओं) का प्रत्युत्तर

- (क) जेमिपोल मै0 श्रीराम की मर्चेट बिक्री का एक प्रमुख खरीदार है। मै0 श्रीराम के पास ऑफर हेतु नगण्य मात्रा होती है।
- (ख) मै0 श्रीराम के अलावा कोई अन्य उत्पादक 295 ली./कि.ग्रा. तथा अधिक गैस पैदावार के कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन नहीं कर सकता है।
- (ग) कैल्शियम कार्बाइड की कीमत गैस पैदावार पर निर्भर करती है।
- (घ) मै0 श्रीराम ने अपनी कारखानागत कीमत दिनांक 1.4.2003 से 1.4.2004 तक 17% बढ़ा दी है।
- (ङ) चीन का कैल्शियम कार्बाइड महंगा हो रहा है क्योंकि चीन की सरकार ने दिनांक 1.1.2000 से निर्यात पर वैट छूट 13% से घटाकर 5% कर दिया है।
- (च) चीन से आयात का मौजूदा सीआईएफ मूल्य 460 अमरीकी डालर प्रति मी.टन है। चीन का घरेलू बाजार कैल्शियम कार्बाइड के सभी प्रीमियम ग्रेडों के लिए ठीक माना जाता है जिसमें 210 ली./किग्रा. से अधिक की गैस पैदावार शामिल होती है जोकि कम गैस पैदावार वाले माल की तुलना में महंगा होता है।

उठाए गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी का प्रत्युत्तर विचाराधीन उत्पाद, समान उत्पादन, घरेलू उद्योग, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षति का आकलन तथा कारणात्मक संबंध के विशेष शीर्षकों के तहत कवर किया गया है।

3. विचाराधीन उत्पाद:

मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद सभी आकारों में कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड ऐसिटीलीन तथा पीवीसी के विनिर्माण हेतु एक आधारभूत औद्योगिक रसायन है। कैल्शियम कार्बाइड के विनिर्माण में प्रयुक्त आधारीक कच्चा माल चूने का पत्थर तथा कार्बन तत्व होते हैं। कार्बाइड से उत्पादित ऐसिटीलीन का प्रयोग कटाई तथा वैल्विंग के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग डिग्रिसिंग/डिसल्फराइजेशन के घटकों के विनिर्माण के लिए भी किया जाता है। प्राधिकारी चाहेंगे कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के अनुसार रखा जाए और इसे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1) में यथाविहित अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता के मुद्दे तक सीमित रखा जाए ताकि ऐसे शुल्क को कम किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

4. समान वस्तु:

नियम 2(घ) के अनुसार¹ समान वस्तु² निम्नानुसार परिभाषित की गई है:-

¹ समान वस्तु का अर्थ उस वस्तु से है जोकि भारत में पाटित की जा रही हो और जो जांच के अधीन वस्तु से हर प्रकार से या तो समान है या मिलती जुलती है या ऐसी वस्तुओं के अभाव में किसी अन्य ऐसी वस्तु से है जो यद्यपि हर तरह से समान नहीं है लेकिन जिसके गुण जांच के अधीन वाली वस्तु से काफी मिलते-जुलते हैं।

अंतिम जांच परिणामों में यह कहा गया कि प्राधिकारी ने यह स्थापित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कैल्शियम कार्बाइड उक्त देशों से निर्यात किए गए कैल्शियम कार्बाइड की समान वस्तु है, भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिक कार्यों तथा उसके उपयोगों/उत्पाद विशिष्टियों तथा कीमत निर्धारण, संवितरण अथवा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे कारकों पर विचार किया। आगे यह भी निर्धारित किया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कैल्शियम कार्बाइड वाणिज्यिक रूप से तथा तकनीकी रूप से भी चीन तथा रोमानिया से आयातित कैल्शियम कार्बाइड द्वारा प्रतिस्थापित करने योग्य है और इस प्रकार यह विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। संबद्ध माल का प्रयोग अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा अलग-अलग आधार पर किया जाता है। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में यह तय किया था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कैल्शियम कार्बाइड संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध

माल की समान वस्तु है। समान वस्तु की संबद्ध शुद्धता विशिष्ट समायोजनों, यदि दावा किया गया, के लिए सर्वोत्तम दर्शाई जा सकती है।

अंतिम समीक्षा की जांच अवधि के दौरान समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। अतः प्राधिकारी चाहेंगे कि समान वस्तु की परिभाषा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1) में यथा व्यवस्था अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता के जांच के प्रयोजनार्थ मूल जांच के अनुसार रखी जाए ताकि ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति को जारी रखने अथवा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके।

5. घरेलू उद्योग

मूल जांच के अंतिम परिणामों में यह कहा गया था कि

.....6. प्रारंभिक जांच परिणामों में यह निर्णय दिया गया था कि याचिकाकर्ता (पनयम सीमेंट को छोड़कर जोकि जांच अवधि के दौरान कैल्शियम कार्बाइड का आयातक रहा है) का घरेलू उत्पादन में 25% से अधिक हिस्सा होता है अतः उसे नियमावली के तहत घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का अधिकार है।

आयातकों द्वारा दिए गए तर्क

7. आयातकों ने यह तर्क दिया है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में कैल्शियम कार्बाइड के कुछ दूसरे छोटे उत्पादनकर्ताओं की अनदेखी की गई है जिनके अस्तित्व को निर्दिष्ट प्राधिकारी और याचिकाकर्ता दोनों ने स्वीकार किया है। आयातकों द्वारा यह भी कहा गया है कि मै0 डीसीएम श्री राम जो जांच अवधि के दौरान कैप्टिव उपभोग के लिए उत्पादनकर्ता के रूप में सूचीबद्ध है, उनके तुलन-पत्र के अनुसार उन्होंने किसी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन नहीं किया है और इस तरह निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जिन आंकड़ों पर निर्भर किया, वेसही नहीं हैं। इसके अलावा टेसिल, बिरला और पैनयाम कैप्टिव उपभोग के लिए उत्पादनकर रहे हैं। लघुस्तर के उद्योगों द्वारा उत्पादन की जा रही कैल्शियम कार्बाइड की एक बड़ी मात्रा को इस कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर की गई गणनासे याचिकाकर्ता कुल घरेलू उद्योग का केवल 31.6% के लिए उत्तरदायी है। शेष 68% से अधिक उद्योग की स्थिति का पता लगाए बिना याचिकाकर्ता जांच कार्रवाई शुरू

करने के लिए अपेक्षित शर्त को पूरा नहीं करता है औरतदनुसार पहली बार में ही इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए ।

8. प्राधिकारी के पास रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा भारत में कैल्शियम कार्बाइड के कुल उत्पादन के बारे में उपलब्ध कराई गई सूचना है । उसमें यह उल्लेख किया गया था कि कैल्शियम कार्बाइड की छः इकाइयाँ हैं । छः में से चार को पहले हीया याचिकाकर्ता (अर्थात् आई सी एम एल, पैनयोम, टेसिल और बिरला कॉर.) के रूप में नामित हैं और अन्य इकाइयाँ मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर एंड कैमिकल और मै. यू.पी. कार्बाइड एंड कैमिकल हैं ।

9. आयातकों के इस दावे के संबंध में, कि प्रारंभिक जांच परिणाम में कैल्शियम कार्बाइड के दूसरे लघु उत्पादनकर्ता की अनदेखी की गई है और यह कि लघुस्तर के उद्योगों द्वारा उत्पादित कैल्शियम कार्बाइड की बड़ी मात्रा को छोड़ दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पार्टियों ने न तो लघु स्तर के उत्पादनकर्ताओं का नाम और पता दिया है और न ही ऐसे लघुस्तर के उत्पादनकर्ताओं द्वारा उत्पादित कैल्शियम कार्बाइड की मात्रा बतायी है । आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के प्रत्युत्तर के अध्ययन के समय प्राधिकारी को कैल्शियम कार्बाइड के ऐसे किसी मुख्य उत्पादनकर्ता के नामका पता नहीं चल सका जिससे ऐसे उपयोक्ता उद्योग को कैल्शियम कार्बाइड की आपूर्ति की हो । प्रारंभिक जांच परिणाम में जितना उल्लेख किया गया है उसके अलावा जांच के दौरान कैल्शियम कार्बाइड के किसी विनिर्माता ने प्राधिकारी के प्रत्युत्तर में कोई समर्थन या विरोध प्रकट नहीं किया है । इसलिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातका यह दावा प्रमाणीकृत नहीं है ।

10. प्राधिकारी ने पाया कि आयातकों का यह तर्क कि श्रीराम फर्टिलाइजर कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन नहीं कर रहा है, वस्तुतः सही नहीं है । मै.श्री राम विनायल एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज (डी सी एम श्री राम कंसोलिडेटेड लिमिटेड की एक शाखा) ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी स्थापित क्षमता 56100 टन है और उन्होंने वर्ष 1996 और 1997 के केवल कैप्टिव उपभासेग के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन किया था । रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने भी यह पुष्टि की है कि डी सी एम श्री राम ने जांच अवधि के दौरान कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन किया है ।

11. एक आयातक ने यह तर्क दिया है कि मै0 आई सीएम एल (एक याचिकाकर्ता) और मै0 चैम प्लास्ट (एक आयातक) दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि इंडिया सीमेंट

लिमिटेड का अध्यक्ष चेमप्लास्ट का एक कार्यकारी उपाध्यक्ष भी है और इंडिया सीमेंट लिमि. का प्रबंध निदेशक चेमप्लास्ट के बोर्ड का निदेश है। इस प्रकार वे एक दूसरे से संबद्ध हैं और इसलिए आई सी एम एल को याचिकाकर्ता के रूप में अयोग्य ठहराया जाए।

प्राधिकारी की स्थिति:

12. प्राधिकारी ने पाया कि नियमानुसार उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से संबंध केवल तभी माना जा सकेगा यदि:

उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे का नियंत्रण करता है, या दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हों, या वे दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रहे हों।

प्राधिकारी ने पाया कि आयातक यह प्रदर्शित और सत्यापित नहीं कर पाए हैं कि या तो चेमप्लास्ट आई सीएम एल का या आई सी एमएल चेमप्लास्ट का नियंत्रण कर रही है। यह भी किसी ने सत्यापित नहीं किया है कि उनमें से दोनों प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं अथवा यह कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति का नियंत्रण कर रहे हैं। दोनों कंपनियों को एक दूसरे से संबद्ध होने की बात केवल इस आधार पर नहीं मानी जा सकती कि उनका एक सांझा कार्यपालक या निदेशक है। यह दिखाने के लिए कि दोनों कंपनियां एक-दूसरे से संबद्ध हैं, उपर्युक्त तीनों में से कोई एक मापदंड पूरा होना चाहिए जो इस मामलों में नहीं हैं और इस प्रकार दोनों कंपनियों को एक दूसरे से संबद्ध नहीं कहा जा सकता है।

13. इसके अलावा, मै0 केमप्लास्ट सनमार लिमि. ने यह स्पष्ट किया है कि यह तर्क/कथन मै0 केमप्लास्ट सेनमार लिमि. द्वारा नहीं दिया गया था।

14. इसे देखते हुए प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को घरेलू उत्पादन के 25% से अधिक के लिए उत्तरदायी माना है और इसलिए इस नियम के अधीन घरेलू उद्योग की ओर से याचिकाकर्ता याचिका दर्ज करने का अधिकार रखता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

मै0 श्रीराम मूल जांच के दौरान एकमात्र कैप्टिव उत्पादक रहा है । उसकी मौजूदा जांच अवधि के दौरान पर्याप्त मर्चेट बिक्री हुई है और इसका मै0 बिरला कार्बाइड (जांच अवधि के दौरान उत्पादन में नहीं रहा), मैसर्स वीबीसी फ़ैरो एलायस (जांच अवधि के दौरान उत्पादन में नहीं रहा) ने समर्थन किया । मैसर्स श्रीराम का देश के कुल 26724 मी.टन के उत्पादन में 16724 मी.टन का दावा है और यह देश में कुल उत्पादन का 62.5% बैठता है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की जरूरत को पूरा करता है । मैसर्स श्रीराम की सहमति को निर्यातक तथा आयातक द्वारा स्वीकृत किया गया है । कैल्शियम कार्बाइड के किसी भी घरेलू उत्पादक ने इसका विरोध नहीं किया । प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत मैसर्स श्रीराम तथा उसके समर्थकों को घरेलू उद्योग मानता है ।

6. पाटन का आकलन - पद्धति तथा कारक

किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है-

- (क) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु के लिए तुलनीय मूल्य जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपयोग के निमित्त हो,
- (ख) जब व्यापार के सामान्य रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री न हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती हो, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया जाए, अथवा
 - (ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत जिसमें प्रशासनिक लागत, बिक्री लागत और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपयुक्त राशि जोड़ी गई हो जिसका निर्धारण उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो;

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से इतर किसी देश से किया गया हो तथा वस्तु को निर्यात वाले देश से होकर केवल बाहानान्तरित किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता हो या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं हो तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

प्राधिकारी ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजी ।

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार:

प्राधिकारी द्वारा जांच: प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि सहयोगकर्ता निर्यातक के व्यवहार के संबंध में इच्छुक पक्षकार द्वारा चीन गणराज्य में गैर-बाजार/बाजार अर्थव्यवस्था की हस्ती के रूप में किए गए निवेदन की जांच की जाए । ऐसे व्यवहार को शासित करने संबंधी संगत नियम निम्नलिखित हैं-

(मामले को आरंभ करते समय भारतीय कानून के तहत स्थिति)

नियम 8(1) शब्द 'गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश' का आशय किसी ऐसे देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत निर्धारण ढांचे के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करने के रूप में निर्धारित करे ताकि ऐसे देश में व्यापार बिक्रियां उप पैरा 3 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार व्यापार के उचित मूल्य को परिलक्षित करे ।

(2) ऐसा भी पूर्व मानना होगा कि यदि किसी ऐसे देश को निर्धारित किया जाए अथवा उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी भी डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच से पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान लिया गया हो ।

किंतु बशर्ते कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा ऐसे देश की संबंधित फर्मों द्वारा इस पूर्व धारणा को निर्दिष्ट प्राधिकारी को जानकारी तथा साक्ष्य प्रदान कर यह

खंडन करे कि ऐसा देश उप-पैरा 3 में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा कि क्या:

(क) कीमतों, लागतों तथा निविष्टियों, कच्चे माल सहित, तकनॉलाजी तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियों तथा पूंजी निवेश के संबंध में ऐसे देश की संबंधित फर्मों के निर्णय सप्लाई तथा मांग को परिलक्षित करने वाले बाजारों संकेतों के प्रत्युत्तर में और इस संबंध में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप के बिना किए गए हों और यह भी कि क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें बाजार मूल्यों को परिलक्षित करती हैं ;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली के बाद पर्याप्त बाधाओं के अध्यक्षीन हैं , विशेष रूप में परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य परिसमापनों, वस्तु व्यापार तथा ऋणों के मुआवजे के जरिए भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्में दिवालियापन तथा संपत्ति कानूनों के अध्यक्षीन हैं जो फर्मों की कानूनी निश्चय तथा स्थिरता की गारंटी देते हैं, और

(घ) मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर के अनुसार किए जाते हैं ।

किंतु बशर्ते कि जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में यह पर्याप्त साक्ष्य दिखाया जाता है कि बाजार दशाएं पाटनरोधी जांच के अध्यक्षीन ऐसी एक या अधिक फर्मों के लिए विद्यमान हैं , निर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों की बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकेगा ।*

दिनांक 10 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना द्वारा अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 में उपर्युक्त नियमावली के उप-पैरा 3 के बाद निम्नलिखित पैरा शामिल किया गया -

* उप पैरा(2) में विहित किसी भी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकेगा जो संगत मानदंडों के अद्यतन विस्तृत मानदंडों के आधार पर, जिनमें उप पैरा(3) में विहित मानदंड शामिल हैं, सार्वजनिक

दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा किसी ऐसे देश द्वारा जोकि विश्व-व्यापार संगठन का एक सदस्य हो, पाटनरोधी जांच के परियोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया हो अथवा माने जाने के लिए निर्धारित हो ।'

7. सामान्य मूल्य (रोमानिया)

मै0 कार्बिड फोक्स, रोमानिया ने प्रत्युत्तर तो भेजा है लेकिन प्रश्नावली का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है । उत्पादन लागत, घरेलू बिक्री कीमत, भारत तथा अन्य देशों के संबंध में बिक्री कीमत के संबंध में कोई जानकारी अथवा ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए । पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) द्वारा प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड करता है ।

पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ रोमानिया में सामान्य मूल्य की गणना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई और इसे डालर ***** /मी.टन आकलित किया गया।

सामान्य मूल्य (चीन जन.गण.)

मै0 टीटीसी तथा मै0 शांक्सी फुगु (निर्यातक तथा उत्पादक) ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर स्तुत किया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी के एक दल ने उनके स्थल का दौरा किया और मूल रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत जानकारी की पड़ताल की । यह पड़ताल मोफकोम, चीन के प्रतिनिधि की मौजूदगी में किया गया । उत्पादन मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्री, भारत को बिक्री तथा अन्य देशों को की गई बिक्री के संबंध में कतिपय त्रुटियां पाई गई । निर्यातक द्वारा ऑफर की गई मै0 टीटीसी तथा तथा मै0 शांक्सी फुगु के बीच बिक्री हेतु संबद्ध माल के हस्तांतरण प्रबंध के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । तुलन-पत्र के आंकड़े प्रश्नावली के प्रत्युत्तर के साथ मेल नहीं खाते थे ।

इन परिस्थितियों में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया और चीन के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया । इस प्रयोजन के लिए सामान्य मूल्य की गणना डालर ***** /मी.टन पर की गई ।

8. निर्यात कीमत (रोमानिया)

मै0 कार्बिड फोक्स ने भारत को किए गए निर्यात के कोई ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए । ऐसा प्रस्ताव है कि रोमानिया के संबंध में निर्यात कीमत की गणना आयात की भारित औसत कीमतों के आधार पर की जाए जैसाकि डीजीसीआईएस ने जांच अवधि के दौरान समुद्री भाड़े, समुद्री बीमे, कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन प्रभार के लिए कारखानागत निर्यात कीमत की गणना के लिए समायोजित की थी ।

इस प्रयोजन के लिए निर्यात कीमत डा. ***** /मी.टन. आती है ।

9. पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पाटन मार्जिन इस प्रकार निर्धारित किया गया है-

अम.डा./मी.टन

देश	चीन जन. गणराज्य	रोमानिया
सामान्य मूल्य	*****	*****
निर्यात कीमत	*****	*****
पाटन मार्जिन	34.8%	60.2%

10. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के विश्लेषण के लिए कारकों की सूचीकृत सारणी नीचे दी गई है । क्षति की अवधि अप्रैल, 1999 से मार्च, 2003 तक है:-

क्षति कारकों (सूचीकृत) का रुझान

व्योरे	इकाई	1999-00	2000-01	2001-02	अक्टूबर-01 मार्च, 03 जांच अवधि	अक्टूबर-01 -मार्च, 03 जांच अवधि वार्षिकीकृत
आयात मात्रा- डीजीसीआई एण्ड एस के अनुसार						
चीन	मी. टन	16501	11733	8898	10101	6734
	%	40.23	34.24	32.74	17.85	17.85
रोमानिया	मी. टन	2098	1894	888	779	519
	%	5.11	5.52	3.26	1	1.37
संबद्ध देश	मी. टन	18599	13627	9786	10880	7253
भूटान	मी. टन	18794	17614	13726	26019	17346
	%	46	51	51	46	45.98
अन्य देश(भूटान को छोड़कर)		3619	3020	3658	19682	13121
सभी खैत	मी. टन	41012	34261	27170	56580	37720
आयात मूल्य- डी जीसीआई एण्ड एस के अनुसार						
चीन	लाख रु.	2200	1686	1430	1496	997
	%	34	27	26	13	13
रोमानिया	लाख रु.	243	217	149	97	65
	%	4	3	3	1	1
संबद्ध देश	लाख रु.	2443	1903	1579	1607	1071
भूटान	मी. टन	3567	3096	3235	5766	3844
	%	55	49	60	51	51
अन्य देश(भूटान को छोड़कर)	लाख रु.	499	1282	598	3856	2571
सभी खैत	लाख रु.	6508	6281	5412	11229	7486
निर्यात कीमत						
चीन	रु./मी. टन	13334	14368	16068	14812	14812
रोमानिया	रु./मी. टन	11569	11443	16776	12474	12474
संबद्ध देश	रु./मी. टन	13135	13962	16132	14767	14767
रु./मी. टन		13334	18976	17577	22160	22160
अन्य देश(भूटान को छोड़कर)	रु./मी. टन	13776	42450	16353	19595	19595
सीमा शुल्क	%	38.5	38.5	30	30	30
लेण्डेड मूल्य-लैडिंग						

प्रमारों सहित						
चीन	रु./मी.टन	18652	20099	21097	19448	19448
रोमानिया	रु./मी.टन	16183	16007	22027	16378	16378
संबद्ध देश	रु./मी.टन	18374	19531	21181	19389	19389
भूटान	रु./मी.टन	18976	17577	23567	22160	22160
अन्य देश(भूटान को छोड़कर)	रु./मी.टन	19271	59381	21471	25816	25816
घरेलू उद्योग पर कुप्रभावकारी आर्थिक कारक						
प्रतिष्ठापित क्षमता	सूचीकृत	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
उत्पादन	सूचीकृत	100.00	110.27	119.12	118.12	118.12
क्षमता उपयोग	सूचीकृत	100.00	110.27	119.12	118.12	118.12
कैपिटिव खपत	सूचीकृत	100.00	117.13	117.86	118.65	118.65
घरेलू बिक्रियाँ	सूचीकृत	100.00	90.75	122.34	116.03	116.03
निर्यात बिक्रियाँ	मी.टन	कोई निर्यात नहीं				
प्रारंभिक शेष	सूचीकृत	100.00	0.00	81.33	0.00	0.00
अन्तिम शेष	सूचीकृत	100.00	-	100.00	100.00	100
बिक्री कीमत	सूचीकृत	100.00	100.00	104.97	102.84	102.56
माल सूची	सूचीकृत	100.00	6100.00	100.00	100.00	100.00
उत्पादन प्रतिदिन	सूचीकृत	100.00	110.27	119.12	118.12	118.12
कर्मचारी	सूचीकृत	100.00	93.17	90.24	81.95	81.95
प्रति कर्मचारी उत्पादन	सूचीकृत	100.00	118.35	132.00	144.14	144.14
लगाई गई पूंजी	सूचीकृत	100.00	102.95	115.08	95.48	95.48
स्वदेशी बिक्री प्रतिदिन	सूचीकृत	100.00	90.75	122.34	116.03	116.03
हास	सूचीकृत	100.00	104.00	131.88	235.67	157.11
कारोबार मर्चेट	सूचीकृत	100.00	95.26	125.81	119.00	119.00
कारोबार में वृद्धि	सूचीकृत	-	-4.74	25.81	19.00	19.00

बिक्री मात्रा में वृद्धि	सूचीकृत		-9.25	22.34	16.03	16.03
हास	सूचीकृत	100	98.64	96.48	106.01	106.01
मांग में बाजार हिस्सा (कैप्टिव खपत सहित)						
याचिकाकर्ता	%	51.11	56.99	63.07	58.86	58.86
चीन	%	15.82	11.40	8.84	6.09	6.09
रोमानिया	%	2.01	1.84	0.88	0.47	0.47
संबद्ध देश	%	17.83	13.24	9.72	6.56	6.56
भूटान	%	18.01	17.12	13.64	15.68	15.68
अन्य देश (भूटान को छोड़कर)		3.47	2.93	3.63	11.86	11.86
सभी आर्यत	%	39.31	33.29	26.99	34.10	34.10
भारतीय उद्योग	%	60.69	66.71	73.01	65.90	65.90
मांग (मर्चेट मांग)	सूचीकृत	100.00	87.64	83.76	98.50	98.50
मर्चेट भाग में बाजार हिस्सा						
याचिकाकर्ता	%	22.03	22.81	32.16	25.95	25.95
चीन	%	25.22	20.46	16.24	10.45	10.45
रोमानिया	%	3.21	3.30	1.62	0.81	0.81
संबद्ध देश	%	28.43	23.76	17.86	11.25	11.25
भूटान	%	28.73	30.72	25.05	26.92	26.92
अन्य देश (भूटान को छोड़कर)		5.53	5.27	6.67	20.36	20.36
सभी आयात	%	62.68	59.75	49.58	58.53	58.53
भारतीय उद्योग	%	37.32	40.25	50.42	41.47	41.47
मजदूरियां	लाख रु०		113.17		239.17	159.45

11. क्षति का आकलन तथा कारणात्मक संबंध

किसी अन्तिम समीक्षा मामले में लागू किए जाने योग्य परीक्षण यह है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के उपबंधों के अनुसार पाटन तथा क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की जाए।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच के उद्देश्य से विभिन्न इच्छुक पक्षकारों की सभी दलीलों पर विचार किया। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा है:-

- (i) कीमत कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की भारित औसत निबल बिक्री वसूली की तुलना आयातों की लैंडिड कीमत से करके किया है जो यह दर्शाता है कि आयातों की लैंडिड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में कम है, इस प्रकार कीमत कटौती चीन के मामले में 10% - 20% के बीच और रोमानिया के मामले में 30% -40% के बीच रही। चीन से होने वाले आयातों के संबंध में कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है और कम कीमत पर बिक्री रोमानिया के मामले में 10-20% के बीच रही है।
- (ii) निबल बिक्री वसूली का निर्धारण छूट/कटौती, कमीशन, शुल्क तथा प्रशुल्क के बिना किया गया। निबल बिक्री वसूली 15,000 मी.टन. से 25000 मी.टन के बीच रही है।
- (iii) पाटन कीमात्रा रोमानिया के मामले में 60.2% और चीन के मामले में 34.8% रही।
- (iv) उत्पादन लागत की गणना सर्वोत्तम क्षमता उपयोग, कच्चे माल की खपत तथा उपयोगिता के आधार पर की गई। इस प्रकार, प्राप्त उत्पादन लागत के आधार पर मै0 श्रीराम ने लाभ कमाया और लगाई गई पूंजी पर आय सकारात्मक पाई गई।
- (v) संबद्ध माल के आयात में समग्र रूप में गिरावट आई जो कुल आयातों के 45% से घटकर जांच अवधि में 19% रह गया।
- (vi) भारत में संबद्ध देशों से होने वाले आयातों का बाजार हिस्सा 17.83% से घटकर 6.56% रह गया।
- (vii) भारत में संबद्ध माल की कैप्टिव खपत को छोड़कर मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयात हिस्से में हालांकि मर्चेट मांग में गिरावट आई है लेकिन यह कमोबेश स्थिर रही।
- (viii) घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्रियों में वृद्धि रही। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी अधिक रहा।
- (ix) याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान मामूली वृद्धि रही।
- (x) संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों द्वारा कीमत कटौती का रुख रहा।
- (xi) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है और उद्योग अब कुछ लाभ कमा रहा है।

- (xii) घरेलू उद्योग ने कारोबार तथा बिक्री मात्रा दोनों दृष्टियों से सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है ।
- (xiii) रोजगार में मामूली गिरावट रही है जबकि उत्पादकता तथा मजदूरी में वृद्धि हुई है ।
- (xiv) भूटान से होने वाले आयात का हिस्सा कुल आयातों में 46% है और ये पाटित आयात नहीं हैं ।
- (xv) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में ऊपर सूचीबद्ध कारकों के अलावा क्षति कारकों की पुनरावृत्ति के संबंध में निर्धारण करने में यह पाया गया कि:
- ◆ चीन तथा रोमानिया से पाटित आयात कम हुए हैं । रोमानिया केवल गैर-परम्परागत किस्में प्रदान कर रहा है ।
 - ◆ चीन जन.गण. की क्षमता विशाल है लेकिन वह कार्बाइड मार्ग का प्रयोग करने वाले अपने पी वी सी संयंत्रों को अधिकांशतः 99% की पूर्ति करता है ।

चीन जन.गण. के व्यापार आंकड़ों से विदित होता है कि चीन में 155 कैल्शियम कार्बाइड संयंत्र हैं और पीवीसी उत्पादन तथा इसके बाद के कार्यों में 4331 संयंत्रों के साथ पीवीसी रेजिन का उत्पादन करने वाले 87 संयंत्र हैं । चीन पीवीसी विनिर्माण के लिए अपने कार्बाइड का एक बड़ा प्रयोक्ता है लेकिन उसके अन्य कार्य भी होते हैं । पड़ताल के दौरान चीन के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा से विदित होता है कि लगभग 5.1 मिलियन मी.टन का उत्पादन वर्ष 2002 में और 6.4 मिलियन मी. टन का उत्पादन 2003 में हुआ । केवल 1.6% (लगभग 83,000 मी.टन) का निर्यात किया जाता है और शेष का प्रयोग अधिकांशतः पीवीसी के उत्पादन तथा अन्य परम्परागत प्रयोगों के लिए किया जाता है । भारत को होने वाले निर्यात उसके कुल उत्पादन का 0.2-0.3% भाग है ।

घरेलू उद्योग ने क्षति की संभावित पुनरावृत्ति के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

- (xvi) कार्बाइड की एक अच्छी खासी मात्रा जो भूटान (72%) तथा चीन (17%) से आ रही है जैसाकि डीजीसीआईएस ने द्वितीय तिमाही 2003 के आंकड़ों में दर्शाई है जिससे कि भारतीय बाजार में उक्त उत्पाद की मांग तथा सप्लाई के अंतर को पूरा किया जा सके ।

निष्कर्ष

पिछले तीन वर्षों में हुई क्षति के आकलन से मालूम होता है कि निबल बिक्री वसूली प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित अक्षतिकारी कीमत की तुलना में अधिक हुई है जोकि कार्बाइड की उत्पादन लागत की तुलना में अधिक है। चीन से होने वाले आयातों के संबंध में कोई क्षति मार्जिन नहीं रहा। कीमत कटौती सकारात्मक है और यह बाजार में कार्बाइड की मांग के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निबल बिक्री मूल्य के निर्धारण से संबंधित है जिसमें कि वृद्धि रही। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन तथा बिक्रियों में बढ़ोतरी रही। कंपनी ने स्वयं दावा किया है कि व्यवसाय कुल मिलाकर अच्छा चल रहा है। जैसाकि घरेलू उद्योग ने सहमति जताई है, घरेलू उद्योग को लगातार कोई क्षति नहीं हुई। मार्जिन की पुनरावृत्ति की आशंका को स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह घरेलू उत्पादन (99%) पर रहा है और चीन में कैल्शियम कार्बाइड की बढ़ती हुई मांग तथा भारत को रोमानिया द्वारा कार्बाइड की गैर-परम्परागत किस्म की सप्लाई के कारण हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाटित आयातों में चीन के मामले में मर्चेट मांग घटकर 10.45% और रोमानिया के मामले में 0.81% रह गया है।

12. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग ऐसीटीलीन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है जिसका उपयोग गैस वैल्विंग में किया जाता है जोकि संबद्ध उत्पाद का सबसे बड़ा उपयोग है। स्पष्ट रूप से कतिपय वैल्विंग कार्यों के लिए एलपीजी के अधिक प्रयोग से भी गैस वैल्विंग प्रयोजनों के लिए कार्बाइड की मांग में वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत में मैसर्स श्रीराम ही एकमात्र एकक है जो कार्बाइड मार्ग द्वारा पीवीसी का उत्पादन कर रहा है। विश्व-स्तर पर तथा देश में पीवीसी की मांग बढ़ रही है। कार्बाइड अधिकांश रूप में एक ऊर्जा गहन उत्पाद है इसलिए बिजली की उपलब्धता तथा लागत कार्बाइड के सभी उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण है। कैल्शियम कार्बाइड के बंद पड़े एककों से बिजली प्रशुल्क, अनियमित सप्लाई, श्रमिक समस्याओं तथा संबद्ध माल के तथाकथित पाटन का मुकाबला नहीं कर सके हैं। वर्ष 2003 की अंतिम दो तिमाहियों में कार्बाइड की सीआईएफ कीमतें निश्चित पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने के बावजूद लगभग 455 अमरीकी डालर मी.टन पर रही। यह कीमत वृद्धि भारतीय प्रयोक्ताओं को कैल्शियम कार्बाइड की उपलब्धता में कमी के साथ जोड़ी गई है।

मै0 श्रीराम को भी प्रचार माध्यमों ने अच्छा लाभ कमाते और अपने पीवीसी संयंत्र के प्रमुख विस्तार की योजना बनाते हुए बताया है । कैल्शियम कार्बाइड की मांग तथा सप्लाई में काफी अंतर है । कैल्शियम कार्बाइड की छोटी-छोटी मात्रा का उत्पादन कर रहे लघु उद्योग एककों की भी कम एसीटीलीन पैदावार है । लघु उद्योग एककों ने प्राधिकारी की जांच में सहभागिता नहीं की है जिससे कि उनके मुद्दों पर ध्यान दिया जाता । इच्छुक पक्षकारों द्वारा कीमत कटौती का लाभ नहीं उठाया गया ।

13. इस प्रयोजन के लिए आयातों का लैंडेड मूल्य भारित औसत आकलनीय मूल्य रहेगा जैसाकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्कों और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत वसूले गए सीमाशुल्क के अतिरिक्त कर को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्कों के लिए यथानिर्धारित है ।

आयातों के लैंडेड मूल्य का निर्धारण सीआईएफ आयात कीमत का निर्धारण सीआईएफ आयात कीमत (डीजीसीआईएस से स्रोत) जमा 1% लैंडिंग प्रभार तथा जांच अवधि के लिए लागू आधारिक सीमाशुल्क के रूप में किया गया है ।

14. अक्षतिकारी कीमत के निर्णय हेतु पद्धति: प्राधिकारी ने जांच अवधि तथा पिछले दो वर्षों की अवधि के लिए घरेलू उद्योग से निर्धारित प्रपत्र में लागत निर्धारण जानकारी मांगी है । प्रस्तावित वास्तविक लागत का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के आधार पर अनुकूल उत्पादन लागत के अनुसार किया गया । घरेलू उद्योग के मामले में एनआईपी के निर्धारण में प्राधिकारी ने सभी संगत कारकों जिनमें कच्चे माल का प्रयोग, जन सेवाओं के प्रयोग तथा जांच अवधि के दौरान वास्तविक प्रभार, पूंजी निवेश, घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ क्षमता उपयोग आदि को ध्यान में रखते हुए यथोचित विश्लेषण किया है । ऐसा प्रस्ताव है कि घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण याचकाकर्त्ता द्वारा लगाई गई पूंजी पर यथोचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

15. निष्कर्ष

- (i) चीन जन.गण. तथा रोमानिया ने भारत में संबद्ध माल का पाटन किया है ।
- (ii) रोमानिया से कोई सहयोग नहीं मिला लेकिन चीन के सहयोगकर्ता निर्यातक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार नहीं किया गया क्योंकि प्रस्तुत आंकड़ों में अनुरूपता नहीं पाई गई ।
- (iii) चीन के मामले में कीमत कटौती नहीं पाई गई जबकि क्षति अवधि के दौरान अन्य क्षति कारकों के विश्लेषण से यह इंगित होता है कि पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं पाया गया जैसाकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है ।
- (iv) घरेलू उद्योग को क्षति जारी नहीं है ।
- (v) घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति की आशंका साबित नहीं हो सकी ।
- (vi) घरेलू उद्योग ने सतत् रूप से अच्छा निष्पादन किया है ।
- (vii) कैल्शियम कार्बाइड के घरेलू उत्पादन तथा कुल घरेलू मांग के बीच काफी अंतर है ।

16. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्कों को जारी रखने से कोई यथोचित प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । प्राधिकारी का विचार है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है । चीन जन. गण. तथा रोमानिया से कैल्शियम कार्बाइड के आयात से संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी की दिनांक 22 जनवरी, 1999 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं० 27/1/97-एडीडी के तहत लगाए गए शुल्क को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सिफारिश की जाती है ।

इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार दायर की जा सकेगी ।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2004

Subject : Anti Dumping Investigations concerning Sunset Review of Anti-Dumping Duty on Imports of Calcium Carbide from China PR and Romania.—Final Finding

No. 15/1/2003-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

1. PROCEDURE

The procedure described below has been followed with regard to the investigation concerning sunset review :

- i. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made thereunder require the Authority to review from time to time , the need for continuance of Anti-Dumping Duty. The Authority had received representations from M/s Shriram Vinyl and Chemicals Industry, had requested for continuance of anti dumping duties after the expiry of the five years period in view of the continued injury to the Domestic Industry.
- ii. The application was supported by M/s Birla Carbide, M/s Vipra Industries, M/s Regency Carbide, M/s Venkateshwara Ferro Alloys, M/s Pee Ell Alloys and M/s VBC Ferro Alloys.
- iii. The Designated Authority initiated Sunset review to review as to whether cessation of the anti dumping duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury as per Section 9A(5) of Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping on Dumped Articles and for Determination of Injury Rules, 1995 the need for continued imposition of the anti dumping duty on imports of Calcium Carbide originating in or exported from People's Republic of China and Romania.

- iv. The Authority issued a public notice dated 20th June, 2003 published in the Gazette of India. Extraordinary, initiating anti dumping investigations concerning Sunset Review. of Anti-Dumping Duty on Calcium Carbide originating in or exported from China and Romania (referred to as the subject country hereinafter). Calcium Carbide is classified under custom heading 284910 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.
- v. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the petitioners and who had participated in the original investigation) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the rule 6(2);
- vi. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers of Calcium Carbide in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
- vii. The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 30th September, 2003. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
- viii. The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with rules 6(3) supra. A copy of the petition was also provided to other interested parties, wherever requested;
- ix. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassies, along with a list of known exporters/producers;
- x. A questionnaire was sent to the following known Exporters / Importer / User / Producer of Calcium Carbide in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4) :
 1. Carbide-Fox S.C.A., Romania
 2. Comchim S.A. Romania
 3. M/s. TTC, & M/s Shaanxi Fugu, China
 4. Munjal gases – Ludhiana
 5. Poona Oxygen & Acetylene Co (P) Ltd
 6. National Oxygen Ltd, Chennai
 7. Asiatic Gases Ltd, Thane
 8. Mapro Industries Ltd, Mumbai
 9. Bombay Oxygen Corpn Ltd., Mumbai
 10. Akshar Acetylene Ltd., Gujarat
 11. BOC Gases Calcutta

12. Gwalior Air Products Ltd., MP
13. Birla Corpn Ltd, A Unit of Birla Carbide, C/o A.K. Gupta
14. TECIL,
15. ICML,
16. Panyam,
17. All India Industrial Gases Manufacturers' Association, New Delhi
18. DCW Limited, New Delhi
19. SENKA Carbon Private Limited, Chennai
20. Shriram Vinyl & Chemical Industries, New Delhi
21. Regency Carbide Pvt. Ltd., Paonta Sahib (H.P.)
22. Venkateshwara Ferro Alloys Pvt. Ltd. Himachal Pradesh
23. Himachal Chamber of Commerce and Industry, Paonta Sahib
24. PEE ELL Alloys Pvt. Ltd., New Delhi
25. Basic Chemicals Pharmaceuticals & Cosmetics Export Promotion Council, Mumbai
26. VBC Ferro Alloys Limited, Hyderabad
27. M/s Chemplast Sanmar
28. M/s Jamshedpur Injection power ltd
29. M/s Vipra Industries ltd

Response in the questionnaire format was submitted only by the following in addition to M/s Shriram:

- a) DCW Limited, New Delhi
- b) SENKA Carbon Private Limited, Chennai
- c) M/s Chemplast Sanmar
- d) M/s TTC and M/s Shaanxi Fugu, China

Although there were support from M/s Birla Carbide, M/s Vipra Industries, M/s Regency Carbide, M/s Venkateshwara Ferro Alloys, M/s Pee Ell Alloys and M/s VBC Ferro Alloys for the petition there was no questionnaire response submitted by the interested parties.

- xi. Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished.
- xii. The Authority conducted on-the-spot investigation at the premises of the producers of Calcium Carbide in India and M/s TTC & M/s Shaanxi Fugu, China.
- xiii. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

- xiv. Cost investigations were also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioners so as to ascertain if anti-dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- xvi. The annexures cited above contain the essential facts under consideration of the Designated Authority, which would form the basis for the Final Findings. The reproduction of statements is not tantamount to either acceptance or rejection of any fact/ argument. Arguments raised by interested parties at the time of the oral hearing are reflected in this Disclosure Statement to the extent that they are considered relevant to these investigations.
- xvii. Investigation was carried out for the period POI starting from 1st October, 2001 to 31st March, 2003 (18 Months).
- xviii. Response to Disclosure Statement was received on 26th March 2004 from
- (a) Domestic Industry
 - (b) M/s ELP on behalf of M/s DCW, M/s Chemplast and M/s Senka (importers/industrial users)
 - (c) M/s Jamshedpur Injection Power Limited (response was received after the stipulated date of 26th March, 2004 on 29th March, 2004)
- xix. The following abbreviations have been used :
- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbide | Calcium Carbide |
| China | The People's Republic of China |
| Authority | Designated Authority |
| USD | US Dollars (1 USD = Rs. 48.59 & 1 USD = RMB 8.26) |
| POI | Period of investigation |
| Final Findings/ Original Case /Investigation | Final Findings Notification of Designated Authority number 27/1/97-ADD dated 22 nd January, 1999 concerning import of Calcium Carbide from the People's Republic of China and Romania |

2. VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY, EXPORTERS & IMPORTERS

2. (A) Views of domestic Industry before issue of disclosure statement

- (i) The exporter can give price undertaking at the prices at which the material has been imported or at non-injurious price.

- (ii) Anti-dumping duty is grossly inadequate hence the duties may be enhanced and recommended for another 5 years.
- (iii) M/s Shriram the petitioner and the domestic industry is suffering injury because of the dumped imports of subject goods from China PR and Romania.
- (iv) M/s Shriram has not made any sales on high sea sale basis although it has imported some Calcium Carbide for its own requirement. Petitioner has not exported any Calcium Carbide.
- (v) Duties may be recommended in US\$.
- (vi) All 15 parameters need to be examined before acceptance of data with regard to MET for China.
- (vii) Inadequate information filed by the exporters.
- (viii) Prices of power in China is equivalent to Rs. 4.00 per unit.
- (ix) Rule 11(3) cannot be applied to recommend duty on regional basis.

2.1 (A) **Views of Domestic Industry after issue of Disclosure Statement**

Views of domestic industry after issue of disclosure statement is as follows:

“.....Petitioner finds that the disclosure statement holds that

- a) *Petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.*
- b) *Product under consideration is being dumped in Indian Market by the exporters from China and Romania. The dumping margins are significant in respect of both the countries. Thus, the exporters continued to dump the material and revocation of ADD would result in further recurrence of dumping.*
- c) *With regard to likelihood of continuance or recurrence of injury, petitioner notes the disclosure statement and submits that*
 - (i) *The price undercutting is in the region of 10-20% in respect of China and 30-40% in respect of Romania;*
 - (ii) *Even though imports have declined in relation to total imports and demand, it is submitted that the decline in imports is due to very imposition of ADD and justifies continuance of ADD. In the absence of ADD, the imports would naturally increase further;*
 - (iii) *It is found that the cost of production was recomputed by the Hon'ble Designated Authority. Petitioner consider that the adjustments to cost of production made by the Designated Authority are not supported with the legal provisions, procedure & practices being followed, uncalled for and without appreciation of relevant peculiar facts & circumstances of this case. Hon'ble Designated Authority has considered power price based on the sale price given in the annual report. However, Hon'ble Designated Authority never called upon the domestic industry to provide relevant information. It is submitted that the petitioner sells power only when it is not able to utilize the power in some of its*

plant. It should be noted Power sold by the company in period of Investigation constitute minimal share of total power produced in period of Investigation.

The Hon'ble CESTAT has held in the matter of Reliance Industries Vs. Designated Authority and Others (relating to PTA) that the power price has to be taken at cost plus profit. Thus, the proposed methodology is inconsistent with the decision of the Hon'ble CESTAT. Petitioner considers that decisions of Hon'ble CESTAT are binding on the Hon'ble Designated Authority.

- (iv) Increase in production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry are not relevant to examine whether cessation of ADD would lead to recurrence of injury to the domestic industry. It is submitted that the domestic industry would not be able to hold on its production, capacity utilization, sales volume and market share in the event of revocation of ADD, as it is established that the landed price of imports is far lower than the net sales realization.*
- (v) Growth and ROI of the domestic industry, which were positive would suffer in case the ADD in force are revoked, as the landed price of imports is far lower than the net sales realization. Revocation of Anti Dumping Duty and likely impact of the same is the relevant parameter and not the actual performance of the domestic industry in the period under reference.*
- (vi) While the domestic industry considers that it is making financial losses, the averment of the Hon'ble Designated Authority that the domestic industry has made profits seems to be based on revised cost of production, where the Hon'ble Designated Authority has, without sufficient basis and reasoning and contrary to the decision of the Hon'ble CESTAT modified the cost of production of the domestic industry. In any event, existence of profits during the period justifies continuance of Anti Dumping Duty, as the imports are undercutting the prices of domestic industry and should the Anti Dumping Duty be revoked, the domestic industry would not be able to hold on the prices and in turn profits.*
- (vii) Even though the domestic industry was able to get some price increase, given the existence of positive and significant price undercutting, it is certain that the domestic industry would not be able to hold on the present prices.*
- (viii) Productivity of the domestic industry would suffer in the event of revocation of domestic industry.*
- (ix) Given very large number of plants in China producing calcium carbide, the country still has surplus carbide, in spite of significant domestic consumption.*
- (d) The domestic industry submits that the present investigations are in the nature of sunset review investigations. Petitioner submits that injury to the domestic industry is required to be examined in the context of the requirements under sunset review. In this regard,*

petitioner submits that the imports are already undercutting the prices of the domestic industry to a very significant extent. Should the present duties be revoked, the extent of price undercutting would further increase, which would most likely result in further increased importance. The performance of the domestic industry was improving and it is most likely that without anti-dumping measures in place, considerable increased volumes of the product concerned would be shipped in the Indian market at very low prices, undercutting the domestic industry prices, thus resulting in recurrence of injury.

The disclosure statement holds that production capacity in subject countries, more particularly in China, for the product under consideration are significantly higher than domestic demand.

Whilst the current duties are insufficient to remove the injury to the domestic industry from these imports and are significantly lower than the dumping margin and injury margins, it is submitted that revocation of measures would lead to further importation of the product in the Country, thus resulting in recurrence of injury to the domestic industry.

- e/ Hon'ble Designated Authority has made certain averments at para 12 of the disclosure statement under the heading "Indian Industry's Interest and Other Issues. It is not clear whether these averments are the views of interested parties or views of Hon'ble Designated Authority. However, petitioner considers that these averments have no relevance to the present investigations. For example, with regard to demand, it is admitted that the demand for carbide has shown positive trend, which is the only relevant factor. The averment that increased use of LPG for certain welding applications has had some impact on demand of the product is not only without any investigation but also uncalled for, as the only relevant factor to the Authority is whether the demand has shown an increase or decline. Averment that use of carbide for production of PVC is "supposed to be" less efficient are based on conjectures, particularly when the petitioner has been producing PVC from this route and does not consider that this route is less efficient.*

Reference of the Hon'ble Authority to current prices of carbide is contrary to established practice of the Authority that developments in the post POI are of no relevance and such a position has been reiterated by the Hon'ble Authority as late as in metcoke, where the Authority declined to take into account sky rocketing prices of the product, holding this to be post POI development.

The disclosure statement contradicts itself when it states at one place that production of PVC through carbide route is "supposed to be less efficient" and it admits that the petitioner is going in for major expansion. It defies any logic to go for major expansion if the route is not efficient. The statement that "SSI units producing small quantities of carbide have low acetylene yield" is again based on conjecture and unsubstantiated evidence on record.

*Non injurious price:- Petitioner are very greatly concerned with the proposed non injurious price for the domestic industry at Rs. 19329 pmt. Petitioner submit that the said determination is after making inappropriate, inadmissible changes in the cost of production, contrary to the directions of the Hon'ble CESTAT in the matter of Reliance Industries Ltd. vs. Designated Authority (relating to PTA, both Spain and Korean case).
.....”*

It is thus evident that the non injurious price has not been appropriately assessed. Petitioner requests reassessment of the non injurious price, considering the cost of production of power with addition for cost of capital and assessment of reasonable profits (on product and power) considering gross fixed assets employed by the Company. The petitioner has done the same and found that the non injurious price considering cost of power and reasonable profit on gross fixed assets of the company comes significantly higher than the non injurious price determined by the Designated Authority.

Net sales realization higher than non injurious price does not imply “no injury”

The present investigations are sunset review investigations. The requirement under sunset review is “continuance” or “recurrence” of “dumping” and “injury”. It is already established by the Hon'ble Authority the product is continued to be sold at dumping prices. Therefore, the only relevant issue becomes injury due to dumping. In this regard, the fact that the net sales realization was higher than non injurious price only establishes, at best, that there was no “continued” injury to the domestic industry. The same does not establish that “injury to the domestic industry would not recur”. Petitioner submits that in case the landed price of imports is significantly lower than net sales realization and non injurious price, it should be concluded that the “injury to the domestic industry would recur” in the event of revocation of Anti Dumping Duty. Significant undercutting implies that the domestic industry would be forced to reduce the prices. Significant positive injury margin implies that the domestic industry would be forced to sell at prices below non injurious price in the even the domestic industry is forced to sell at matching prices. Thus, given the positive undercutting and injury margin, petitioner submits that the injury to the domestic industry would recur in the event of revocation of Anti Dumping Duty.”

Examination of Authority (2.1 A above)

Response of Authority to the views expressed by domestic industry after the disclosure statement was issued, based on response of domestic industry, verification of records of domestic industry by Authority and other facts available:

- (a) Details of arriving at the cost of production was explained to the domestic industry with respect to each element of the costing after the non-injurious price was confidentially disclosed to domestic industry, especially in respect of cost of power and treatment of assets. There has been no change in stand of Authority and Authority relied on information submitted by domestic industry.
- (b) The injury parameters were assessed based on the submissions made by the domestic industry, claims of M/s Sriram in its various annual reports and data collected during verification. Detailed assessment is covered under the relevant paragraph (11) of this finding

- (c) Published annual report of M/s Sriram (2001-02) claims that “demand is also showing a declining trend in view of substitution by LPG.” Which has been relied upon by Authority for its specific observation.
- (d) No information was submitted by any of the supporting domestic producers on the like products its usage or on the prescribed questionnaire by Authority. Information was largely received from the user industry only.
- (e) Domestic industry itself agreed in its response to the disclosure statement, to the fact that the assessment of injury parameter establishes that there was no “continued” injury to the domestic industry. With regards to recurrence of injury separate parameters have been examined under para (11) of this finding.
- (f) Issue of gas yield of carbide and production and market of PVC was brought out by the importers/users.
- (g) Information related to period after POI has not been considered by Authority for injury assessment, it has been referred to while describing issues pertaining to Indian industry’s interest.

2. (B) Views of Export/Importer/User. Views of exporter/importer/users before issue of disclosure statement

(i) M/s Carbid-Fox Romania: (Exporter)

- (a) Subsequent to imposition of Antidumping duty. Carbide exports to India reduced from 17% to 3.23%.
- (b) Delivery of unconventional sorts of Carbide are only made now by Romania.
- (c) Prices at which it is supplied to India are normal and much higher than the prices of Calcium Carbide originating from China.
- (d) “.....Information about production, export, prices, delivery markers etc., we consider being confidential and with all respect, we cannot provide it.....”

2.1 (B) Views of M/s Carbid Fox (Exporter)after issue of Disclosure Statement

M/s Carbid Fox submitted a detailed reply after disclosure was issued which was disregarded as no information was provided by M/s Carbid Fox during the investigation period from 20th June 2003 to 17th March 2004 (date of issue of disclosure statement).

(ii) Views of Export/Importer/User. Views of Export/Importer/User before issue of disclosure statement M/s TTC & M/s Shaanxi Fugu (Exporter);China & Importers

- (a) Non-confidential information of the petition is wholly inadequate.
- (b) M/s Shriram is an importer for trading purposes.
- (c) State of the Domestic Industry is not clear.
- (d) Product under consideration is not a radio active material.
- (e) Normal value of the subject goods should be determined on the basis of actual costs and market economy treatment be granted to China.
- (f) There is acute shortage of Calcium Carbide. Despite ADD in place the importers are importing carbide from China.

- (g) There is no producer of carbide in South India which effects users of Carbide in South India.
- (h) Public interest should be considered by DA.
- (i) There is no injury to domestic industry and figures provided by petitioner are misleading.
- (j) There is no causal link between dumped goods and injury caused to domestic industry, if any.
- (k) Special and differential treatment may be granted for different users (market) in South India vide Rule 11(3).
- (l) Electricity cost for M/s Shriram is not reflected properly.
- (m) International and Chinese Prices are Market Driven.
- (n) DGCIS trade data should be considered.
- (o) Domestic industrial users are willing to purchase from M/s Shriram assuming they engage in fair pricing and are able to commit large quantities in a timely manner.
- (p) Non-cooperating company should not be granted the residual category.
- (q) Anti-dumping duty should not be recommended any further.

2.1 (B) Views of the importer/users after issue of Disclosure Statement

Views of importer/users after issue of disclosure statement is as follows:

".....With reference to the above, the following is submitted on behalf of the Importers/Industrial Users:

1. Confidential Information:

- a) *At the outset it must be emphasized that the information provided in the petition, as well as at every stage of the proceeding has been woefully inadequate and has not provided any opportunity for the Industrial Users to effectively counter the claims made by the Petitioner. In particular the following has not been provided to the Industrial Users:*
 - *Indexed formats of the costing information to be provided with the petition.*
 - *Division wise balance sheet and profit and loss accounting, pertaining to the production of calcium carbide by the Petitioner.*
 - *Methodology for determining the NIP of the Petitioner, in particular apportionment of the overhead costs and the costs of electricity.*
 - *Realization from the captively consumed calcium carbide by the Petitioner.*

Each one of these issues indicated above, go to the root of the Investigation and non-disclosure of these issues are prejudicial to the Industrial Users.

- b) *Further pursuant to clause xi under the heading PROCEDURE, the Hon'ble Designated Authority has stated that additional information on injury was sought from and provided by the Petitioner. No non-confidential version of the same was made available to the Industrial Users.*

2. Domestic Industry and Demand:

- a) *At the outset, it must be stated that the factors under consideration by the Hon'ble Designated Authority concerning the composition of Domestic Industry is incomprehensible for the most part.*
- b) *Without prejudice to the aforesaid, it is respectfully submitted that the conclusions drawn by the Hon'ble Designated Authority are prima facie erroneous. The Hon'ble Designated Authority has concluded that M/s Shriram, along with its supporters M/s VBC Ferro Alloys and M/s Birla Carbide is untenable. Admittedly the latter two were not in production during the Period of Investigation. For the record the two supporters have not produced any calcium carbide since the Period of Investigation, as well as during the Period of Investigation. By taking in to consideration their installed capacity and giving them status of the Domestic Industry is a travesty to the consumers of Calcium Carbide in India.*
- c) *Clearly, there is huge demand supply gap in the country. By classifying non-producers as Domestic Industry, the Hon'ble Designated Authority is severely damaging consumers of Calcium Carbide in India.*

3. Fixation of Normal Value from China:

- a) *The Hon'ble Designated Authority has noted that during the verification visit to China, the only exporter cooperating in this proceeding was unable to provide suitable details to verify the costs submitted by it during the course of the proceeding.*
- b) *It is most respectfully submitted that the Industrial Users of Calcium Carbide have received a serious set back. The other exporters had categorically refused to cooperate in this proceeding. By disqualifying the only cooperating exporter, the Hon'ble Designated Authority has set the stage for continuation of the duty for another five years.*
- c) *It is respectfully submitted that the Hon'ble Designated Authority should not disregard the information made available by the cooperating exporter. Under Rule 6(8) which provides:*

In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances,

The Hon'ble Designated Authority is fully able to utilize independent costs, such as costs of electricity, transportation, packaging etc. which are prevailing in China, which were provided by the partially cooperating exporter, as these will be supported by independent invoices.

- d) *It is earnestly requested that the Hon'ble Designated Authority give effect to these values, as any eventual duty based on the costs provided by the Petitioner will be devastated.*

4. Injury:

- a) *It is respectfully submitted that the Petitioner has not suffered any injury, on the contrary has had record earnings.*

- b) First, the Industrial Users wish to re-iterate the submissions made vide letter dated 10th March 2004. In particular, the Industrial Users wish to put on the record, the press releases showing the record profits and expansion planned by the Petitioner. Clearly, this is not the sign of a company suffering any injury. A copy of the letter along with its annexures are attached herewith as Annexure I.
- c) The Hon'ble Designated Authority has recorded that during the Period of Investigation that:
- Production is up.
 - Capacity utilization is up.
 - Captive consumption is up.
 - Opening stock is down.
 - Selling price is up.
 - Daily production is up.
 - Capital employed is down.
 - Indigenous sales per day are up.
 - Turnover is grown.
 - Sales volume have grown.

In light of the above, it is respectfully submitted that the Domestic Industry has suffered no injury and accordingly the duty should be withdrawn.

5. Causal Link:

- a) With reference to the above, it is respectfully submitted that the Petitioner's injury if any, has not been caused by the alleged dumping from China or Romania.
- b) Import volumes have decreased. In fact the Hon'ble Designated Authority has noted that the share in the merchant market for China has decreased from 25.22% to 10.45%. In the case of Romania, the share in the market has come down from 3.21% to 0.81%. By the same token the share of the Petitioner has increased and is above 25%. In the total demand, similarly, the share of China has decreased from 15.82% to 6.09% and Romania from 2.01% to 0.47%. The Petitioner's share remains in excess of 56%. Thus, the Petitioner has over 82% of the market share. This is all the more noteworthy given the fact that the Petitioner remains the only producer of Calcium Carbide in the country, since all others closed down due to internal difficulties or prohibitively high costs of electricity.
- c) Further, the Hon'ble Designated Authority must consider the role played by the exports from Bhutan – exports from Bhutan continue to have a robust market share, and the landed value of the Calcium Carbide from Bhutan, although apparently high, does not attract CVD (Excise) in India and thus effectively comes in at virtually the same price as the material from China and Romania.

6. Recent Developments, Injury and Threat Thereof:

- a) It must be pointed out that in the recent months, the costs of Calcium Carbide from China have touched appx. US\$450/- on a CIF basis. Attached herewith as Annexure 2 are actual invoices (Confidential) showing details of recent imports made by the Industrial Users.
- b) Attached herewith as Annexure 3 are recent quotations received from China.

- c) Further, attached herewith as **Annexure 4** (Confidential) are communications with the various suppliers speaking of delayed shipments and shortages in China.
- d) It is a fact that the Hon'ble Designated Authority can verify independently that the Chinese Government has imposed Anti Dumping Duty on Calcium Carbide originating in South Korea, exported to China. As a consequence of this, all domestic production of Calcium Carbide in China is diverted to use for PVC production in China and there is supply shortage in the export market. Further, to increase the supply of Calcium Carbide in the domestic Chinese market, the Chinese Government has withdrawn the VAT incentives, that were being provided to exporters, similarly to the withdrawal of DEPB to steel exporters in India.
- e) The Industrial Users have already been subjected to Anti Dumping Duty for over five years (the Hon'ble Designated Authority extended the levy pending this sunset review beyond the initial five years) and now the prices are astronomically high....."

Examination of Authority (2.1 B above)

Response of Authority to the views expressed by importer/users, after the disclosure statement was issued, is based on response of importer/users, verification of records of exporter by Authority and other facts available:

- ◆ Detailed methodologies adopted by Authority for determination of non-injurious price, landed value, net sales realization have been disclosed in the disclosure statement and in this finding.
- ◆ A complete indexed injury chart on a time series was disclosed as essential fact. The questionnaire prescribed (available in public domain) for domestic industry has forms CI and CII which clearly indicates the methodology adopted by Authority for apportionment of the overhead costs. Confidentiality has been granted to information as per para 6 (general) of the anti-dumping application proforma. Exporter was informed of the observations of Authority during verification soon after the verification.
- ◆ The disclosure statements issued to domestic industry has details of non-injurious price confidentially communicated to domestic industry. The methodology was explained to the domestic industry separately.
- ◆ Specific disclosure of methodology of arriving at and details of export price and normal value have been made available to the exporter.

2.2 (B) Response to remaining issues raised are contained under the specific headings of product under consideration, Normal value, export price, assessment of injury and causal link and Indian industry's interest and other issues.

2.3 Response of Jamipol (Users)

Views of importer/user after issue of disclosure statement is as follows:

- (a) Jamipol is one of the major buyers of merchant sales of M/s Sriram. M/s Sriram have "negligible quantity to offer".
- (b) No other producer but for M/s Sriram can produce Calcium Carbide of gas yield 295 Lts/kg and above.
- (c) The price of Calcium Carbide depends on gas yield.
- (d) M/s Sriram has increased its ex-works price by 17% from 1.4.2003 to 1.4.2004.
- (e) Chinese Calcium Carbide is becoming expensive because Chinese government has reduced VAT exemption on the export from 13% to 5% with effect from 1.1.2004.

- (f) Current CIF value of import from China is US\$460/MT. Chinese domestic market is considered to be that of most premium grade of Calcium Carbide with gas yield of over 310 lts/kg which is more expensive than the material with lesser gas yield.

Response of Authority to the issues raised is covered under the specific headings of product under consideration, like article, domestic industry, normal value, export price, injury assessment and casual link.

3. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration for the purpose of present investigation is calcium carbide of all sizes. Calcium carbide is one of the basic industrial chemicals for manufacture of Acetylene and PVC. The basic raw materials used in manufacture of calcium carbide are limestone and carbon matter. Acetylene produced from Carbide is used for cutting and welding. Calcium Carbide is also used to manufacture degreasing/desulphurisation agents. The Authority would retain the scope of product under consideration as in the original investigation and limit itself only to the issue of the need for continued imposition of the anti dumping duty as envisaged in Section 9A (5) of Custom Tariff Act and Rule 23(1) of Anti-Dumping Rules such that cessation of such duty does not lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. LIKE ARTICLE

As per Rule 2(d), "Like Article" has been defined as under :-

"Like Article" means an article which is identical or alike in all respect to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respect, has characteristics closely resembling to those articles under investigation."

In the Final findings it was held that Authority considered factors such as physical characteristics, manufacturing process and technology functions and uses, product specification and pricing, distribution and tariff classification of goods in order to establish whether the calcium carbide produced by domestic industry is a Like Article calcium carbide exported from said countries. It was further held that calcium carbide produced by the domestic industry is substitutable by the calcium carbide imported from China and Romania both commercially and technically and thus a Like Article to the product under consideration. The subject goods are used by end users interchangeably. In the Final Findings the Authority held that Calcium Carbide produced by the Domestic Industry is a Like Article to the subject goods imported from the subjects countries. Relative purity of the Like Article may at best be addressed by providing for specific adjustments if claimed.

During the Period of Investigation of the Sunset review there are no changed circumstances with respect to the issue of Like article hence Authority would retain the definition of like article as in the original investigation for purposes of examination of the need for continued imposition of the anti dumping duty as envisaged in Section 9A(5) of Custom Tariff Act and

Rule 23(1) of the Anti-Dumping Rules such that cessation of such duty does not lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. DOMESTIC INDUSTRY

In the final findings of the original investigation it was stated that

“ 6. It was held in the preliminary findings that the petitioner (excluding Panyam cement who is an importer of Calcium Carbide during the period of investigation) accounts for more than 25% of domestic production and therefore has a standing to file a petition on behalf of domestic industry under the rules.

Arguments raised by Importers

7. It is argued by the importers that preliminary findings ignore several other small producers of Calcium Carbide whose existence is acknowledged by Designated Authority and petitioner. It is also stated by importers that M/s DCM Shri Ram who were listed as producer for captive consumption during the period of investigation have not produced any quantity of Calcium Carbide as per their balance sheet and thus the figures relied upon by Designated Authority are not accurate. In addition Tecil, Birla and Panyam are producing for captive consumption. A large quantity of Calcium Carbide being produced by small-scale industries has been left out of these proceedings. Calculated on these facts, the petitioner accounts for only 31.6% of the total domestic industry. Without ascertaining the stand of over 68% of the remaining industry, the petitioner does not meet the condition required for the initiation and accordingly be void ab-initio.

Authority Position

8. The Authority has the information made available by Department of Chemical and Petrochemical on the total production of Calcium Carbide in India. It was reported therein that there are six units of Calcium Carbide. Out of six, four are already named as petitioner (viz. ICML, Panyam, Tecil and Birla Corp) and others are M/s Shri Ram Fertilizer & Chemical and M/SU P carbide and chemical.

9. Regarding the claim of the importers that preliminary findings ignore other small producer of calcium carbide and that large quantity of calcium carbide being produced by small scale industries has been left out, the Authority notes that the interested parties have neither given the names and address of small scale producers nor the quantum of production of calcium carbide by such small scale producers. While going through the responses to questionnaire filed by the importers, the Authority could not find the name of any major producer of calcium carbide who had supplied the calcium carbide to such user industry. No other calcium carbide manufacturer had responded to Authority regarding support or opposition during the investigation except to the extent specified in the preliminary findings. Therefore the Authority notes that this claim of the importer is not substantiated.

10. The Authority observes that the argument of importers that Shri Ram Fertilizer is not producing Calcium Carbide is factually incorrect. It is confirmed by M/s Shri Ram Vinyl & Chemical Industries (A division of DCM Shri Ram consolidated Ltd.) that their installed

capacity is 56100 tonnes and they produced Calcium Carbide in the year 1996 and 1997 for captive consumption only. The Department of Chemical & Petrochemical has also confirmed that DCM Shriram is producing Calcium Carbide during the period of investigation.

11. An importer has argued that M/s ICML (a petitioner) and M/s Chemplast (an importer) are related, as the Chairman of India Cement Ltd. is also an executive vice President of Chemplast, and the Managing Director of India Cement Ltd. is a Director on the Board of Chemplast. Thus they are related and therefore ICML be disqualified from being a petitioner.

Authority's Position :

12. The Authority observes that as per rules, the producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if :

One of them directly or indirectly controls the other or

Both of them are directly or indirectly controlled by a third person or

Together they directly or indirectly control a third person

The Authority observes that importer has not demonstrated and established that either Chemplast controls ICML or ICML controls Chemplast. Also it is neither established that both of them are directly or indirectly controlled by a third person nor that together they directly or indirectly control a third person. Two companies can not be stated to related to each other merely on the ground that they have a common executive or director. To demonstrate that two companies are related, any of the three criteria stated above should be fulfilled which is lacking in this case and thus these two companies can not be stated to be related to each other.

13. Moreover, M/s Chemplast Sanmar Ltd. has clarified that this arguments/statement was not made by M/s Chemplast Sanmar Ltd.

14. In view of this, the Authority hold that petitioner accounts for more than 25% of domestic production and therefore have a standing to file the petition on behalf of domestic industry under the rules."

Examination by Authority

M/s Shriram was a solely captive producer during original investigation. It has adequate merchant sales during the present POI and is supported by M/s Birla Carbide (not in production during POI), M/s VBC Ferro Alloys (not in production during POI). Claims of 16724 MT of production by M/s Shriram of total 26724 MT in the country comprises 62.5% of the total production in the country and satisfies the requirement of Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules. Contention of M/s Shriram is also accepted by the exporter and importer. There was no opposition from any domestic producers of Calcium Carbide. Authority considers M/s Shriram along with supporters comprising domestic industry under Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules.

6. Assessment of dumping - Methodology and Parameters

Normal value in relation to an article implies

- (a) Comparable price, in ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory.
- (b) When there are no sale of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market, of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country, or
 - (b) The cost of production of the subject goods in the country of origin along with reasonable addition for the administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)

Provided that in the case of imports of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with section with 9A(1)(c) of the Custom Tariff Act.

MARKET ECONOMY TREATMENT :

Examination by Authority : The authority proposes to examine the submission made by the interested party with regard to the treatment of the cooperating exporter as Non Market/ Market economy entity in China PR. Relevant Rules governing such treatment are as under:

(Position Under Indian Law at time of initiating matter):

Rule 8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not

reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country.

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether :

(a) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate:

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph".

Vide Notification dated 10th November, 2003 the following paragraph was inserted paragraph 8 of Annexure – 1, after sub-paragraph (3) of *Rules Supra*.

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2). The Designated Authority may treat such country as market economy country which, on the bases of the latest detail evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub-paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

7. Normal Value (Romania)

M/s Carbid Fox from Romania had responded but did not provide any questionnaire response. No information and details related to cost of production, domestic sales price, sales price to India and other countries was provided. Vide Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules the Designated Authority records its findings on the basis of the facts available to it.

For the purpose of Dumping Margin normal value in Romania was constructed on the basis of the facts available and was found to be \$*****/MT.

Normal Value (China PR)

M/s TTC & M/s Shaanxi Fugu (Exporter and Producer) had submitted the questionnaire response. A team of Designated Authority visited the site and verified the information submitted with the original records. The verification was done in the presence of representative of MOFCOM, China. Certain discrepancies with regards to volumes of production, sales in the domestic market, sales to India and sales to other countries were observed. No satisfactory reply to the transfer arrangement of subject goods for sale between M/s TTC and M/s Shaanxi Fugu could be offered by the exporter. The Balance sheet figures did not tally with the questionnaire response.

Under the circumstances the data supplied by the exporter was disregarded and the normal value was constructed for China based on facts available. Normal value for the purpose comes out to \$*****/MT.

8. Export Price (Romania)

No details of exports to India was provided by M/s Carbide Fox. Export price for Romania was constructed on the basis of weighted average price of imports as shown by DGCIS during POI adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation, port expenses to arrive at ex-factory export price.

The export price for the purpose comes out to \$*****/MT.

Export Price (China PR)

As discussed in para under Normal value the information provided by exporter did not tally with the records verified at their premises (including sales volumes) hence Authority constructed export price on the basis of weighted average price of imports as shown by DGCIS during POI adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation, port expenses to arrive at ex-factory export price.

The export price for the purpose comes out to \$*****/MT.

9. DUMPING MARGIN:

Considering the normal value and export price, as detailed above, dumping margin have been determined based on constructed normal value and export price.

US\$/ MT

Country	China PR	Romania
Normal Value	*****	*****
Export Price	*****	*****
Dumping Margin	34.8%	60.2%

10. Indexed table of the parameters to analyze injury to the Domestic Industry because of Dumped imports is as follows. The injury period is from April 1999 to March 2003.

Trend of injury parameters (Indexed)

Particulars	Unit	1999-00	2000-01	2001-02	Oct-01 - Mar 03 POI	Oct-01 - Mar 03 POI Annualized
Imports Qty - As per DGCI&S						
China	MT	16501	11733	8898	10101	6734
	%	40.23	34.24	32.74	17.85	17.85
Romania	MT	2098	1894	888	779	519
	%	5.11	5.52	3.26	1	1.37
Subject Countries	MT	18599	13627	9786	10880	7253
Bhutan	MT	18794	17614	13726	26019	17346
	%	46	51	51	46	45.98
Other Countries-(Except Bhutan)		3619	3020	3658	19682	13121
All Sources	MT	41012	34261	27170	56580	37720
Imports Value - As per DGCI&S						
China	Rs Lacs	2200	1686	1430	1496	997
	%	34	27	26	13	13
Romania	Rs Lacs	243	217	149	97	65
	%	4	3	3	1	1
Subject Countries	Rs Lacs	2443	1903	1579	1607	1071
Bhutan		3567	3096	3235	5766	3844
	%	55	49	60	51	51
Other Countries-(Except Bhutan)	Rs Lacs	499	1282	598	3856	2571
All Sources	Rs Lacs	6508	6281	5412	11229	7486
Export price						
China	Rs./MT	13334	14368	16068	14812	14812
Romania	Rs./MT	11569	11443	16776	12474	12474
Subject Countries	Rs./MT	13135	13962	16132	14767	14767
Bhutan	Rs./MT	18976	17577	23567	22160	22160
Other Countries-(Except Bhutan)	Rs./MT	13776	42450	16353	19595	19595
Customs Duty						
	%	38.5	38.5	30	30	30
Landed Value - Including 1% Landing charges						
China	Rs./MT	18652	20099	21097	19448	19448
Romania	Rs./MT	16183	16007	22027	16378	16378
Subject Countries	Rs./MT	18374	19531	21181	19389	19389
Bhutan	Rs./MT	18976	17577	23567	22160	22160
Other Countries-(Except Bhutan)	Rs./MT	19271	59381	21471	25816	25816
Economic Parameters Affecting the domestic industry						
Installed Capacity	Indexed	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Production	Indexed	100.00	110.27	119.12	118.12	118.12
Capacity Utilization	Indexed	100.00	110.27	119.12	118.12	118.12

Captive Consumption	Indexed	100.00	117.13	117.86	118.65	118.65
Indigenous Sales	Indexed	100.00	90.75	122.34	116.03	116.03
Export Sales	MT	No exports				
Opening Stock	Indexed	100.00	0.00	81.33	0.00	0.00
Closing Stock	Indexed	100.00	-	100.00	100.00	100
Selling Price	Indexed	100.00	104.97	102.84	102.56	102.56
Inventories	Indexed	100.00	6100.00	100.00	100.00	100.00
Production per Day	Indexed	100.00	110.27	119.12	118.12	118.12
Employees	Indexed	100.00	93.17	90.24	81.95	81.95
Production per Employee	Indexed	100.00	118.35	132.00	144.14	144.14
Capital Employed	Indexed	100.00	102.95	115.08	95.48	95.48
Indigenous Sales per day	Indexed	100.00	90.75	122.34	116.03	116.03
Depreciation	Indexed	100.00	104.00	131.88	235.67	157.11
Turnover (Merchant)	Indexed	100.00	95.26	125.81	119.00	119.00
Growth in Turnover	Indexed	-	-4.74	25.81	19.00	19.00
Growth in Sales Volume	Indexed	-	-9.25	22.34	16.03	16.03
Demand	Indexed	100	98.64	96.48	106.01	106.01
Market share in Demand – (including captive consumptions)						
Petitioner	%	51.11	56.99	63.07	56.86	56.86
China	%	15.82	11.40	8.84	6.09	6.09
Romania	%	2.01	1.84	0.88	0.47	0.47
Subject Countries	%	17.83	13.24	9.72	6.56	6.56
Bhutan	%	18.01	17.12	13.64	15.68	15.68
Other Countries-(Except Bhutan)		3.47	2.93	3.63	11.86	11.86
All Imports	%	39.31	33.29	26.99	34.10	34.10
Indian Industry	%	60.69	66.71	73.01	65.90	65.90
Demand (Merchant demand)	Indexed	100.00	87.64	83.76	98.50	98.50
Market share in Merchant Demand						
Petitioner	%	22.03	22.81	32.18	25.95	25.95
China	%	25.22	20.46	16.24	10.45	10.45
Romania	%	3.21	3.30	1.62	0.81	0.81
Subject Countries	%	28.43	23.76	17.86	11.25	11.25
Bhutan	%	28.73	30.72	25.05	26.92	26.92
Other Countries-(Except Bhutan)		5.53	5.27	6.67	20.36	20.36

All Imports	%	62.68	59.75	49.58	58.53	58.53
Indian Industry	%	37.32	40.25	50.42	41.47	41.47
Wages	Rs. Lacs		113.17		239.17	159.45

11. Assessment of Injury and Causal Link

The test which is required to be applied in a sunset review case is to, examine the likelihood of *continuation or recurrence* of dumping and injury in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act.

The Authority considered all the arguments of various interested parties for examination of injury to the domestic industry. The Authority considered the following parameters while examining injury to the domestic industry:-

- (i) Price undercutting was determined by comparing the weighted average net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports which shows that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry, resulting in price undercutting in the range of 10%-20% in case of China and in the range of 30%40% in case of Romania. Price undercutting is related to the net sales realization of the domestic industry. The net sales realization value would largely depend on the best sales price negotiated by the domestic industry as a result of demand and supply of Carbide in the domestic market, According to M/s Shriram its product did command a premium in the market. There is no price underselling with regards to imports from China but there is price underselling in the range of 10-20% in case of Romania.
- (ii) The net sales realization was determined exclusive of rebates/discounts, commission, taxes and duties. Net sales realisation is in the range of Rs. 15000/MT to 25000/MT
- (iii) Dumping margin is 60.2% in case of Romania and 34.8% in case of China PR. The margin of dumping has been computed based on constructed cost of production, normal value and export price.
- (iv) Cost of production was computed based on the best capacity utilisation, consumption of raw material and utility. Based on the cost of production thus arrived at, profit was incurred by M/s Shriram and return on capital employed was found to be positive.
- (v) Imports of subject goods have decreased in absolute terms from 45% of total imports to 19% in POI.
- (vi) Market share of imports from the subject countries to the total domestic demand in India have decreased from 17.83% to 6.56% .
- (vii) The share of imports from the subject countries in relation to demand excluding captive consumption of subject goods in India has decreased although Merchant demand (demand excluding captive consumption of the domestic industry) has by and large remained constant.
- (viii) Production, capacity utilization and sales of the domestic industry has increased. The capacity utilization of the domestic industry remained very high.
- (ix) The selling price of the petitioner has undergone slight increase during the injury period.

- (x) The selling price of the domestic industry has increased and the industry is making some profits.
- (xi) The domestic industry has posted positive growth, both in terms of turnover and sales volume.
- (xii) Employment has slightly decreased where as productivity and wages have increased.
- (xiii) Imports from Bhutan which comprise 46% of total imports are not dumped imports.
- (xiv) In making a determination for recurrence of injury factors other than listed above relating to the impact of dumped imports on the domestic industry it was observed that Domestic industry has not provided any evidence regarding likelihood of recurrence of injury.

- ◆ Dumped Imports have come down from China and Romania. Romania is only providing unconventional sorts.
- ◆ Capacity of China PR is huge but it caters largely (99%) to its PVC Plants using the Carbide route.
- ◆ There are no anti dumping measures in force for dumping of carbide to countries other than India.

China trade data reveals China has 155 Calcium Carbide units and has 87 plants producing PVC resins with 4331 plants on PVC production and downstream application. China largely remains a big user of its own carbide for PVC manufacture however, its other applications are also there. Discussions with Chinese officials during verification revealed that approximately 5.1 million MT was produced in 2002 and 6.4 million MT was produced in 2003. Only 1.6% (approx 83000 MT) is exported and the remaining carbide is used domestically largely for production of PVC and other conventional usages. Exports to India only forms 0.2-0.3% of its total production.

- (xv) There is still a good quantum of Carbide coming from Bhutan (72%) and China (17%) as shown by DGCIS data for 2nd Quarter, 2003 to fill up the gap in demand and supply of the said product in Indian Market.

Conclusion

The injury assessment over period of three years reveals that the net sales realization is higher than non-injurious price determined for the domestic industry by Authority which in turn is higher than the cost of production of carbide. There is no injury margin with respect to imports from China. Price undercutting is positive and is related to the fixing of net sales realization by domestic industry with respect to the demand of carbide in the market, which has increased. Capacity utilization, production and sales of domestic industry has increased. Company has itself claimed that the segment business as a whole is doing very well. As agreed by domestic industry, there is no continued injury to the domestic industry. Chances of recurrence of dumping could not be clearly established because of huge (99% of domestic production) and growing domestic demand of Calcium Carbide in China and supply of only unconventional sort of carbide by Romania to India. More importantly dumped imports have

come down to 10.45% of merchant demand (6.09% of total demand) in case of China and 0.81% (0.47% of total demand) in case of Romania.

12. Landed value of imports for the purpose of the injury analysis was the weighted average assessable value as determined by the customs under the Custom Tariff Act, 1962 and all duties of custom except Additional duty of Custom levied under section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Custom Tariff Act, 1975.

The landed value of imports has been determined as the CIF import price (sources from DGCIS) plus 1% landing charges and applicable basic customs duties for the POI.

13. **Indian Industry's interest and other issues**

Calcium Carbide can be used for production of acetylene which is used for gas welding which is the single largest use of the subject products. Apparently, increased use of LPG for certain welding applications has also had negative impact on growth of demand of Carbide for gas welding purposes. M/s Shriram is the only unit in India producing PVC through Carbide route. Globally as well as within the country PVC has a growing demand. Carbide is largely an energy intensive product hence availability and cost of electricity is critical to all producers of Carbide. The closed domestic units of Calcium Carbide have largely not been able to cope up with high electricity tariff, irregular supply, labour problems and alleged dumping of subject goods. CIF prices of Carbide in the last two quarters of 2003 have touched almost \$455/MT despite fixed anti dumping duties in place. The price rise is coupled with shortage of availability of Calcium Carbide to Indian users.

M/s Shriram is also reported by media to having incurred good profits and going in for major expansion plan of their PVC Plant. There is a huge gap between demand and supply of Calcium Carbide. The SSI units producing small quantities of Calcium Carbide have low acetylene yield. The SSI units did not participate in the investigation for Authority to take a closer look at their issues. Price undertaking was not availed of by the interested parties.

14. **Methodology for arriving at non injurious price** : The Authority has called for the costing information from the domestic industry in the prescribed Proforma for the period of investigation and the previous two year. The actual cost of proposed to be used to determine optimum cost of production on the basis of Generally Accepted Accounting Principal (GAAP). In the determination of NIP for the domestic industry, the Authority has made appropriate analysis of all the relevant factor including usage of raw material, the usage of utilities the actual expenses during the POI, The investment, the capacity utilization etc to arrive at NIP for domestic industry. The NIP for the domestic industry is proposed to be determined considering a reasonable profit margin on the capital employed by the petitioner.

15. Conclusion

- (i) China PR and Romania have dumped the subject goods to India.
- (ii) There was no cooperation from Romania. The information submitted by the cooperating Chinese exporter was disregarded because of the inconsistencies in the data submitted.
- (iii) There is no price underselling with regards to China. An analysis of other injury parameters over the injury period indicates no causal link between the dumped imports and the injury claimed by the domestic industry.
- (iv) There is no continued injury to domestic industry.
- (v) Likelihood of recurrence of dumping and injury to domestic industry could not be established.
- (vi) Domestic Industry has consistently performed well.
- (vii) There is a gap between domestic production and total domestic demand to Calcium Carbide.

16. In view of the above Authority concludes that continuation of the duties would serve no reasonable purpose. Authority is of the view that the cessation of such duty is not likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Duties vide Final Findings Notification of Designated Authority number 27/1/97-ADD dated 22nd January, 1999 concerning import of Calcium Carbide from the People's Republic of China and Romania is recommended to be withdrawn with immediate effect.

An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority